राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख...

पेज | 06-09

वर्ष 6 अंक 08

16-31 अक्टूबर, 2025 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

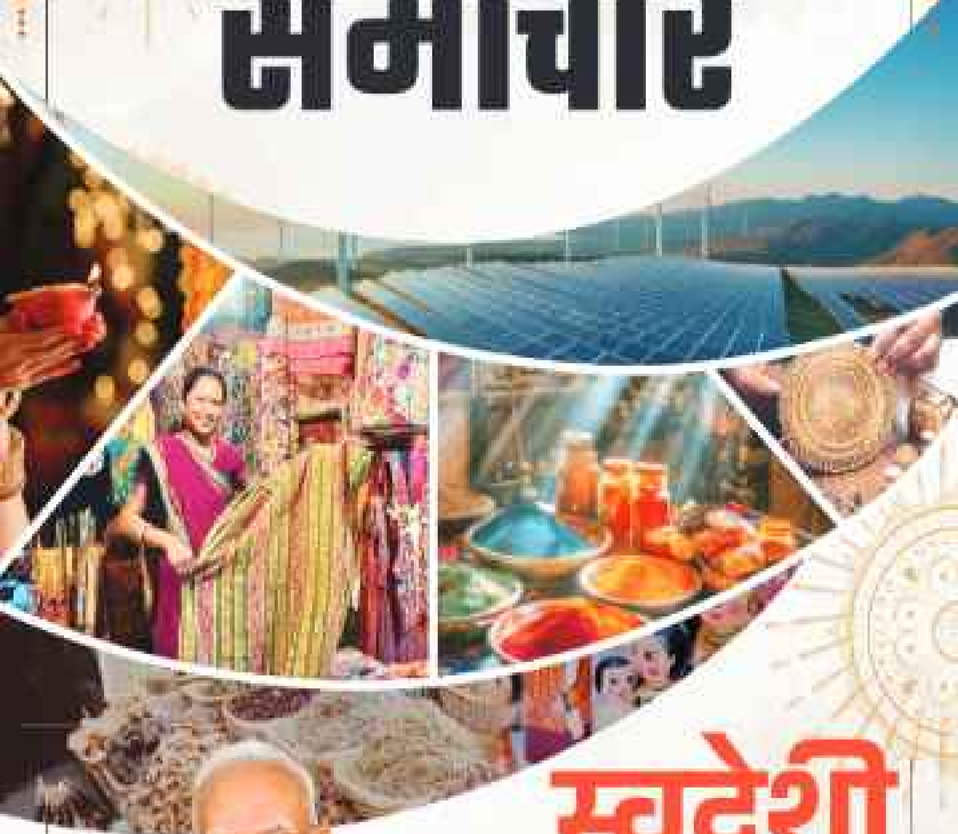

स्वदेशी

समृद्धि का मार्ग

देश की समृद्धि को मिल रही स्वदेशी के मंत्र से शक्ति और 140 करोड़ नागरिकों के प्रयास से अब राष्ट्र का हर उत्सव बन रहा है समृद्धि का महोत्सव...

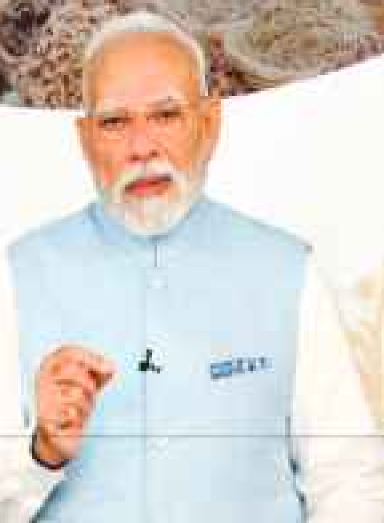

ई-कॉपी के लिए स्कैन करें

...तो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होगा छठ महापर्व

'मन की बात' कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए देशवासियों से जुड़ने, उनसे सीखने, देश के लोगों की उपलब्धियों के बारे में जानने-समझने का एक बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला माध्यम बन गया है। अपनी बातें साझा करते हुए 'मन की बात' कार्यक्रम का 126वां एपिसोड 28 सितंबर को पूरा हुआ है। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर, महर्षि वाल्मीकि, भूपेन हजारिका, गायक जुबीन गर्ग के असामयिक निधन के साथ-साथ महत्वपूर्ण पर्वों पर चर्चा की तो वहीं छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही, कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने विचार साझा किए। प्रस्तुत है मन की बात के संपादित अंश...

- **शहीद भगत सिंह :** अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज हैं। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट-कूट कर भरी थी। भगत सिंह लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे।
- **लता मंगेशकर की जयंती :** 28 सितंबर लता मंगेशकर की जयंती। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थीं।
- **वीर सावरकर से प्रेरित :** लता मंगेशकर ने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। लता दीदी जिन महान विभूतियों से प्रेरित थीं उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थीं। उन्होंने वीर सावरकर के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया।
- **बेटियों का परचम :** व्यापार से लेकर खेल तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए - देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वे ऐसी चुनौतियों को भी पार कर रही हैं, जिनकी कल्पना तक मुश्किल है।
- **वैश्विक त्योहार बनती छठ पूजा :** छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दीपावली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग-अलग हिस्से में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह एक वैश्विक त्योहार बन रहा है।
- **यूनेस्को सूची :** भारत सरकार छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। जब छठ पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे।
- **कोलकाता की दुर्गा पूजा :** कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस सूची का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी।
- **खादी की बिक्री :** महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद, खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी लेकिन बीते 11 साल में इसके प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है।
- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :** इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष रही। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हुए हैं। एक शताब्दी की यह यात्रा जितनी अद्भुत, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख यही संघ की सच्ची ताकत है। आरएसएस सौ वर्षों से बिना थके, बिना रुके, राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है।
- **सफाई जिम्मेदारी :** त्योहारों पर हम सब अपने घर की सफाई में जुट जाते हैं। लेकिन स्वच्छता सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित न रहे। गली, मोहल्ला, बाजार, गांव हर जगह पर सफाई हमारी जिम्मेदारी बने।

मन की बात पूरी सुनने के लिए इस कोड को स्कैन करें

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष 6, अंक 08 | 16-31 अक्टूबर, 2025
प्रधान संपादक
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

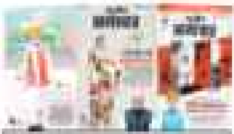

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए फॉलो करें @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

[illegible] | 12-25

समाचार सार | 4-5
राष्ट्र साधना के 100 साल
[illegible] | 6-9
एक भारत-श्रेष्ठ भारत : एकता का राष्ट्रीय उत्सव
[illegible] | 10-11
[illegible] | 26-27
[illegible] | 28-31
[illegible] | 32-33
[illegible] | 34-35
[illegible] | 36-37
[illegible] | 38-39
[illegible] | 40-41
[illegible] | 42-43
[illegible] | 44-45
[illegible] | 46-47
[illegible] | 48-49
[illegible] | 52

[illegible] | 30-31

प्रधानमंत्री का पत्र

[illegible] | 3

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, बीओसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। मुद्रक: [illegible] नई दिल्ली-110020। प्रकाशन और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-277, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003। ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर: DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

स्वदेशी संग त्योहार बन रही जीवनशैली

सादर नमस्कार।

भारत त्योहारों-उत्सवों का देश है और उत्सव हम सभी के जीवन में एक नई चेतना जगाने वाला अवसर होता है। इस वर्ष की दिवाली विशेष है क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सेना के पराक्रम से जगमगाती दिवाली है। इस ऑपरेशन से दुनिया ने भारत के स्वदेशी की ताकत देखी है। स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान-पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। भारत के सामर्थ्य की इस ऊंचाई ने दुनिया को दो-टूक संदेश दिया है- "भारत की कहानी आज मजबूत है, कल और भी मजबूत होगी।" बीते कुछ वर्षों में यह परिवर्तन आया है तो उसका कारण है- 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी संग उत्सव', जो अब जन सेवा, देश सेवा का माध्यम बन चुका है। स्वदेशी के संग, उत्सव के रंग ने स्थानीय उत्पादों और भारतीय बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। जहां रोजमर्रा के जीवन की हर जरूरत के लिए स्थानीय वस्तुओं की खरीद को लेकर उत्साह राष्ट्र की समृद्धि का मंत्र बन गया है।

दरअसल, आत्मनिर्भरता का मार्ग स्वदेशी से ही होकर जाता है और यही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि का माध्यम बना है। आज त्योहार ही नहीं, सभी अवसरों पर स्वदेशी देश के लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। स्वदेशी खरीदना, स्वदेशी बेचना, राष्ट्र के प्रति गर्व की अनुभूति कराता है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते एक दशक से अधिक के कालखंड में स्वदेशी की पहल राष्ट्र समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख, देश के जवानों के संग पीएम मोदी की दिवाली पर एक विशेष रिपोर्ट भी इस अंक में शामिल है। व्यक्तित्व की कड़ी में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण, फ्लैगशिप में उड़ान योजना के 9 वर्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री शामिल है। 6जी की स्वदेशी तकनीक की शुरुआत सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रम को इसमें जगह दी गई है।

इसके अलावा, पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात, जीएसटी बचत उत्सव पर देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और बैक कवर पर जीएसटी बचत उत्सव पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेंद्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात....

प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला। मुझे यह पत्रिका बहुत पसंद आई। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार है। मुझे इस पत्रिका का हमेशा इंतजार रहता है। पत्रिका में देश की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न विकास कार्यों के बारे में सरल भाषा में जानकारी मिलती है।

vahidrahman786@gmail.com

भारत की प्रगति और पीएम मोदी के कार्यों का स्पष्ट चित्रण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नया अंक प्राप्त कर बहुत खुशी हुई। मुझे हर बार इस पत्रिका का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले 11 वर्षों की भारत की प्रगति और पीएम मोदी के कार्यों की स्पष्ट जानकारी मिली। यह मेरे जैसे लोगों और समाज को जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इस पत्रिका में काम करने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।

arddkumar@rediffmail.com

योजना और देश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानने का माध्यम

केंद्र सरकार की योजना, कार्यक्रम और देश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी के लिए, न्यू इंडिया समाचार पत्रिका एक बेहतरीन माध्यम है। यह पत्रिका बहुत बेहतरीन है। मैं चाहता हूं कि नियमित रूप से यह पत्रिका मुझे मिलती रहे, ताकि मैं देश में हो रहे विकास कार्य एवं योजनाओं से अवगत रह सकूं।

kamalkishor2mit@gmail.com

सभी लेख अत्यंत सूचनाप्रद, ज्ञानवर्द्धक एवं प्रेरक प्रसंगों से परिपूर्ण

गांव में प्रवास के दौरान मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला। यह पत्रिका कई दृष्टिकोण से अद्वितीय है। मुख्य कवर और गुणवत्ता छपाई के साथ ही सभी लेख सूचनाप्रद, ज्ञानवर्द्धक एवं प्रेरक प्रसंगों से परिपूर्ण है। अब मैं नियमित रूप से यह पत्रिका पढ़ना चाहता हूं। साथ ही संपादक मंडल से मुझे अपने व्यावसायिक बंधुओं से भी अनुरोध करना कि वो नियमित रूप से इसे पढ़ें।

pamishra1959@gmail.com

मिलती है विकास के बारे में उपयोगी एवं तथ्यपरक जानकारी

मैं एक सेवानिवृत्त व्याख्याता हूं। हाल ही में मुझे आपकी पत्रिका न्यू इंडिया समाचार पढ़ने का अवसर मिला। मुझे यह एक बेहतरीन पत्रिका लगी। सरकारी नीतियों को समझने का यह एक बेहतरीन माध्यम है। इसमें नई नीतियों, सामाजिक मुद्दों, विकास और सरकार द्वारा की गई कई अन्य पहलों के बारे में उपयोगी एवं तथ्यपरक जानकारी पढ़ने को मिलती है।

gnarayanan79@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पताः कमरा संख्या- 1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. ईमेल- response-nis@pib.gov.in

[illegible]

वंदे मातरम्

150 गौरवशाली वर्ष का मनेगा उत्सव

[illegible]

समाचार सार

प्रगति की 49वीं बैठक

ताकि न चुकानी पड़े देरी की दोहरी कीमत

[illegible]

[illegible]

देश में पहली बार...

ट्रेन से मिसाइल दागने का परीक्षण सफल

[illegible]

उज्ज्वला परिवार का विस्तार... निःशुल्क मिलेंगे 25 लाख नए कनेक्शन

[illegible]

यूनेस्को की संभावित सूची में 7 प्राकृतिक विरासत शामिल

भारत अपनी अद्भुत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लगातार स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण की इस कड़ी में अब भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, अब इस सूची में भारत के विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। इनमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित विरासत स्थल शामिल हैं। यूनेस्को ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार, विश्व विरासत सूची में नामांकित होने के लिए किसी भी स्थल का संभावित सूची में शामिल होना आवश्यक है। विश्व विरासत सूची में भारत की 44 प्रॉपर्टीज शामिल हैं।

संभावित सूची में दर्ज नई धरोहर

- महाराष्ट्र में पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप
- कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत
- मेघालय में मेघालय युग की गुफाएं
- नागालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट
- आंध्र प्रदेश में एर्रा मट्टी दिब्बालु
- आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत
- केरल में वर्कला चट्टानें

भगवान बुद्ध की विरासत को बढ़ावा प्रदर्शनी के लिए रूस भेजे अवशेष

सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक मंच पर बौद्ध विरासत के प्रसार को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत ने रूस के काल्मिकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे इन अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से काल्मिकिया की राजधानी एलिस्टा भेजा गया। बता दें कि काल्मिकिया में 24 से 28 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध फोरम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से भगवान बुद्ध के जीवन की चार महान घटना को दर्शाती मूर्तियां और कलाकृतियों की तीन प्रदर्शनियां लगाई गईं। एक अन्य प्रदर्शनी शाक्य लोक की राजधानी, प्राचीन कपिलवस्तु, पिपरहवा से शाक्यों की पवित्र विरासत : बुद्ध अवशेषों की खुदाई और प्रदर्शनी पर आधारित रही। इस मंच पर 30 से अधिक देशों के आध्यात्मिक गुरु और अतिथि एक साथ आए। उम्मीद है कि इस दौरान इन बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया, ब्यूरेशिया और किस्तान भी ले जाया गया है।

'वेवएक्स' ने की सात नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर वेवएक्स ने मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी-एवीजीसी एक्सआर सेक्टर के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए सात नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। आईआईआईटी दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद, कोझिकोड, अमरावती, आईआईआईटी पुणे और एफटीआईआई कोलकाता में स्थापित होने वाले ये सात केंद्र मीडिया, गेमिंग और एवीजीसी स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। स्टार्टअप को फिल्म निर्माण, गेम डेवलपमेंट, संपादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए उन्नत सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। ये सात केंद्र भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई के अंतर्गत होंगे। वेवएक्स का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और नवा टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है। यह पहली बार है जब टेक्नोलॉजी (एवीजीसी-एक्सआर, डिजिटल मीडिया, प्रसारण और इमर्सिव टेक्नोलॉजी) क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से एक समर्पित प्लेटफॉर्म तथा इनक्यूबेशन तंत्र शुरू किया गया है।

राष्ट्र साधना के 100 वर्ष

इस विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 100 वर्ष का हो गया। संघ का शताब्दी वर्ष साक्षी है राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना का, जिसने स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के पंच परिवर्तन के सूत्रों पर चलते हुए सदैव राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी है। आरएसएस की समर्पित यात्रा राष्ट्र की सेवा में गौरवमयी स्वर्णिम पृष्ठ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, जिसका ध्येय समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। आज भारत प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है तो उसमें भारत और विश्व के लाखों स्वयंसेवकों का योगदान है, जिन्होंने न केवल सामाजिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में अहम की भूमिका निभाई है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पण भाव से जुड़े हैं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया तो अगले दिन 2 अक्टूबर को आलेख के जरिए अपने मन के भाव किए प्रकट...

100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के महापर्व पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय-समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए-नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने मिल रहा है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रसेवा के संकल्प को समर्पित कोटि-कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं संघ के संस्थापक, हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संघ की 100 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए हैं।

जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी सैकड़ों जीवन पुष्पित-पल्लवित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के

सहस्राब्दी तक प्रभाव डालने वाली संघ की शताब्दी यात्रा...

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया।
- स्मारक सिक्के में एक ओर भारत का राष्ट्रीय चिह्न, जबकि दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की तस्वीर और श्रद्धा से उन्हें नमन करते स्वयंसेवक हैं।
- डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना स्वयंसेवक-आधारित संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था।
- इसके साथ जारी डाक टिकट में स्वयंसेवकों की ऐतिहासिक तस्वीर को परिलक्षित किया गया है। इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में विभिन्न भूमिकाओं में राष्ट्रीय सेवा के दृष्टिकोण को आत्मसात करने वाली प्रतिबद्धता को दिखाया गया है।
- संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है।
- संघ का अंतिम लक्ष्य भारत की 'सर्वांगीण उन्नति' है, जिसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक स्वयं को समर्पित करता है। पिछली शताब्दी में, आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- इसके अलावा, आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत करने में योगदान दिया है।
- शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इसके स्थायी योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी प्रदर्शित करता है।

अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला। ये उद्देश्य रहा- राष्ट्र निर्माण

अलग-अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तीकरण जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है...राष्ट्र प्रथम।

अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण का विराट उद्देश्य लेकर चला। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना और इस पथ पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य-नियमित चलने वाली शाखाएं। संघ शाखा का मैदान, एक ऐसी प्रेरणा भूमि है, जहां से स्वयंसेवक की अहम् से वयम् की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञवेदी हैं।

राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य, व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल, जीवंत कार्यपद्धति यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बनी। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। संघ पथ के अस्तित्व में आने से संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही। आजादी की लड़ाई के समय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई में कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। आजादी के बाद भी संघ निरंतर राष्ट्र साधना में लगा रहा। इस यात्रा में संघ के खिलाफ साजिशें भी हुईं, संघ को कुचलने का प्रयास भी हुआ। ऋषितुल्य परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया। क्योंकि वो जानते हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं, समाज हमसे ही तो बना है। समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थितप्रज्ञ रखा है, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है।

प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। हर आपदा में संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े रहे। यह केवल राहत नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना...ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। आज भी प्राकृतिक आपदा में हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक होते हैं।

अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में संघ ने समाज के अलग-अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है...जो दुर्गम हैं जहां पहुंचना सबसे कठिन है। संघ...दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति-रिवाज, आदिवासी मूल्यों को सहेजने-संवारने में अपना सहयोग देता रहा है...अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज सेवा भारती...विद्या भारती, एकल विद्यालय...वनवासी कल्याण आश्रम...आदिवासी समाज के सशक्तीकरण का स्तंभ बनकर उभरे हैं।

समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो

ऊंच-नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, वो हिन्दू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही हैं। ये एक ऐसी गंभीर चिंता है, जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक, संघ की हर महान विभूति ने, हर सर-संघचालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर 'न हिन्दू पतितो भवेत्' की भावना को आगे बढ़ाया। पूज्य बाला साहब देवरस जी कहते थे- छुआछूत अगर पाप नहीं, तो दुनिया में कोई पाप नहीं! सरसंघचालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट लक्ष्य रखा है।

जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे, लेकिन आज 100 वर्षों बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तब आज के समय की चुनौतियां अलग हैं, संघर्ष अलग हैं। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। मुझे यह खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोडमैप बनाया है। संघ के पंच परिवर्तन, स्व बोध, सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के सामने उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा हैं।

स्व बोध की भावना का उद्देश्य गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व और स्वदेशी के मूल संकल्प को आगे बढ़ाना है। सामाजिक समरसता के जरिए वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रण है। आज हमारी सामाजिक समरसता को घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। देश ने भी इससे निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें कुटुम्ब प्रबोधन यानी परिवार संस्कृति और मूल्यों को भी मजबूत बनाना है। नागरिक शिष्टाचार के जरिए नागरिक कर्तव्य का बोध हर देशवासी में भरना है। इन सबके साथ हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

अपने इन संकल्पों को लेकर संघ अब अगली शताब्दी की यात्रा शुरू कर रहा है। 2047 के विकसित भारत में संघ का हर योगदान, देश की ऊर्जा बढ़ाएगा, देश को प्रेरित करेगा। पुनः प्रत्येक स्वयंसेवक को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ■

प्रधानमंत्री का पूरा आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत

एकता का राष्ट्रीय उत्सव

ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावे स दुर्बलः।
तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्र हितैषिणः॥

अर्थात्, किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता होती है। इसलिए मजबूत राष्ट्र के हितैषी एकता की इस भावना की प्रशंसा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। देश की एकता और एकजुटता हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए केंद्र सरकार ने एकीकृत व्यवस्था और एकता के सूत्र में बांधने वाली पहलों से एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को दी है मजबूती...

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर और 'राष्ट्रीय एकता दिवस' यह केवल तारीख भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता सदा-सर्वदा विशेषता और विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, अंतर्मन में रची बसी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में सरदार पटेल के जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इन 12 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। गुजरात का केवड़िया तो आज 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना का, नए भारत की शक्ति का तीर्थस्थल बन गया है। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहां का एकता नगर, भारत के एक ऐसे मॉडल शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अद्भुत है। लोगों की एकता से, जनभागीदारी की शक्ति से विकसित होता एकता नगर, आज भव्य और दिव्य भी हो रहा है।

देश के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल से जुड़े सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय आ सकते हैं। यहां पहली बार एआई-होलोग्राफिक पहल से लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवंत जैसे 3डी अवतार के साथ इंटरैक्टिव बातचीत कर पाएंगे।

राष्ट्र अपनी एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर पिछले वर्ष से ही 2 वर्षीय उत्सव मना रहा है। दो वर्ष का यह उत्सव, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के संकल्पों को मजबूती प्रदान कर रहा है। पिछले वर्ष केवड़िया में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष के उत्सव का ऐलान किया था। जब भारत को आजादी मिली थी, तब दुनिया में कुछ लोग थे, जो भारत

12वें एकता दिवस पर एक भारत-श्रेष्ठ भारत के 12 प्रतीक

1. एक देश-एक आइडेंटिटी : आधार की व्यवस्था ने देश के डिजिटल को नई दिशा दी है और सुविधा इसकी पहचान बनी है।

2. एक देश-एक टैक्स : पहले भारत में अलग-अलग टैक्स सिस्टम की जटिलताएं थी [illegible] एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ।

3. एक देश, एक पावर ग्रिड : एक पावर ग्रिड से देश के सभी हिस्सों में बिजली [illegible] सुनिश्चित हो रही है।

4. एक देश, एक राशन कार्ड : एक देश एक राशन कार्ड ने देश के अंदर [illegible]

5. एक देश, [illegible] : [illegible]

6. एक देश-एक हेल्थ इंश्योरेंस : आयुष्मान भारत से आज देश के [illegible] नागरिकों के लिए [illegible] मुफ्त इलाज सुविधा।

7. एक देश, एक मोबिलिटी कार्ड : पूरे देश में मेट्रो, बस, ट्रेन, पार्किंग और सभी [illegible] राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) [illegible]

8. एक देश, [illegible] : [illegible]

9. एक देश, एक परीक्षा : राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी [illegible] केंद्रीय नौकरियों के लिए अलग-अलग परीक्षा के जाल से मुक्ति।

10. एक देश-एक [illegible] : [illegible]

11. एक देश-एक डिजिटल कोड : [illegible]

12. एक देश, एक संविधान का संकल्प भी पूरा : आजादी के 7 दशक बाद जम्मू-कश्मीर ने सम्पूर्णता में भारतीय संविधान को अपनाया। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद यह संभव हुआ। यह सरदार पटेल और बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है।

के बिखरने का आकलन कर रहे थे। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके, फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा लेकिन सरदार पटेल ने यह कर दिखाया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार पटेल... व्यवहार से यथार्थवादी... संकल्प से सत्यवादी... कार्य से मानवतावादी... और ध्येय से राष्ट्रवादी थे। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त, समावेशी, संवेदनशील, सतर्क, विनम्र हो और विकसित भी हो। उन्होंने देशहित को हमेशा सर्वोपरि रखा।

बीते 11 वर्षों की यात्रा भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में, राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे... 'विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी। इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है।' बीते 11 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों से एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। केवड़िया में बीते वर्ष पीएम मोदी ने कहा था कि आजादी के 7 दशक बाद, देश में एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है और यह सरदार पटेल की आत्मा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जम्मू-कश्मीर में पिछले चुनावों में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने इसे संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि बताया। बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज

"आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है कि वन नेशन, वन विधान। हम सरदार साहब के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे और यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए।"

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। पूर्वोत्तर में भी संकट थे... विकास और विश्वास से, सरकार ने उन को हल किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू-रियांग समझौते के कारण हजारों विस्थापित लोग दशकों बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने अशांति खत्म की है।■

स्वदेशी

भारत की समृद्धि का महोत्सव

उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, दीवाली वहां जो भारत में बनी झालरों से हो - और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो 'यह स्वदेशी है'। इस भाव को लेकर नया भारत आगे चल रहा है जिसका एक ही मंत्र है- 'वोकल फॉर लोकल', एक ही मार्ग है- 'आत्मनिर्भर भारत', एक ही लक्ष्य है 'विकसित भारत'। इस त्योहार और शादियों के मौसम में आइए जानते हैं कि कैसे स्वदेशी बीते 11 वर्षों की यात्रा में आत्मनिर्भर भारत का बन गया है आधार...

भविष्य में कुछ खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिससे बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। नया भारत इसी संकल्प और मंत्र को लेकर चल रहा है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत का मार्ग आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और 'आत्मनिर्भर भारत' का सबसे बड़ा आधार बन गया है- स्वदेशी। इस संकल्प ने जन-जन के मन में भारत को विकसित बनाने का भाव भर दिया है। आज तन स्वदेशी, मन स्वदेशी और कण-कण स्वदेशी के भाव से भरा हुआ है तो उसका कारण है- बीते 11 वर्षों में 'वोकल फॉर लोकल' जन-जन की आवाज बना है और जब 'स्वदेशी मेरा उत्पाद' जन सेवा, देश सेवा का जरिया बन रहा है। जहां रोजमर्रा के जीवन की हर जरूरत के लिए स्थानीय वस्तुओं की

कृषि

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और समृद्धि की धुरी है। पिछले ग्यारह वर्षों में, ओवरऑल रूप से विशेषज्ञ प्रयास कृषि में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने वाले किसानों के प्रति राष्ट्र का दृष्टिकोण बदला है। अब वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार और भारत के विकास के वाहक के रूप में देखे जाते हैं। आज भारत किसान हितों को प्राथमिकता देने के साथ खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर और खाद्य उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए है तैयार.

खाद्यान्न उत्पादन

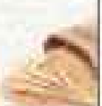

2013-14	246.42 मिलियन टन
2024-25	353.96 मिलियन टन

63.57%

बढ़ा है देश में दुग्ध उत्पादन बीते दशक में। डेयरी क्षेत्र में 8 करोड़ किसान कार्यरत। दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान है।

निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी

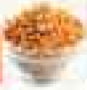

2013-14	13.7%
2024-25	20.4%

- वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है।
- 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत। अगस्त 2025 तक किसानों को 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग 20.4% है।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 2014 से पिछले 11 वर्षों में मछली उत्पादन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 140% की वृद्धि हुई है।
- भारत ने 2022-23 में 1.42 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया और 79,929 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया।

1,37,756 करोड़ रुपये हो गया 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट, 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये था।

खरीद को लेकर उत्साह ही राष्ट्र के हर त्योहारों का नया मंत्र बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की समृद्धि का मार्ग स्वदेशी को बताया था। उसी पर आगे चलते हुए आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। किसानों, मछुआरों, पशुपालकों और उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

यह दीपावली का त्योहार, छठ महापर्व, उसके बाद शादियों का समय और भी विशेष बनने वाला है। 'भारत प्रथम' सिद्धांत के साथ 'वोकल फॉर लोकल' अभियान ने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ 140 करोड़ देशवासियों को एक विशेष संकल्प के साथ न केवल जोड़ा है, बल्कि स्थानीय उत्पादों के प्रति रुझान भी बढ़ा दिया है। अब देश के नागरिक स्थानीय चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। केवल त्योहार ही नहीं, स्वदेशी को हर समय जीवन का मंत्र बनाने का

रक्षा क्षेत्र

आयातक से आगे बढ़ निर्यातक का सफर

ऑपरेशन सिंदूर के साथ दुनिया ने भारत की ताकत देखी। यह ऑपरेशन स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन का सबसे बड़ा ... साबित हुआ। इसके पीछे है बीते एक दशक की वह प्रतिबद्धता, जिस पर चल कर ... दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक भारत ने निर्यातक का सफर तय किया है।

रक्षा बजट

स्वदेशी रक्षा उत्पादन

रक्षा उत्पाद निर्यात

- 65% रक्षा उपकरण अब भारत में ही बन रहे, जबकि पहले 65 से 70% आयात किए जा रहे थे।
- तेजस और प्रोजेक्ट ... के साथ ... जैसे उपकरण देश में ही बन रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर के जरिए देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- रक्षा उत्पादन में इनोवेशन के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) की पहल।
- देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक एफडीआई और सरकारी मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत से अधिक एफडीआई की अनुमति।
- भारत अब आर्मेनिया, फ्रांस, फिलीपींस व अमेरिका जैसे 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।
- निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों में बुलेटप्रूफ जैकेट, डोर्नियर डीओ-228 विमान, चेतक हेलिकॉप्टर, तेज इंटरसेप्टर बोट, और हल्के टॉरपीडो शामिल हैं।
- सुदर्शन चक्र मिशन के जरिए वर्ष 2035 तक स्वदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनाने की शुरुआत की।

रक्षा क्षेत्र से जुड़े **5,012** आइटम स्वदेशी उत्पादों के रूप में पहचान की गई।

आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक और आह्वान किया था- वेड इन इंडिया। उनका कहना था कि अब विदेशों में जाकर शादियां करके देश का धन मत लुटाओ। देश में अच्छी-अच्छी जगह है, उसे डेस्टिनेशन बनाएं। इसका परिणाम हुआ कि आज लोग विदेश में शादी के आयोजन से परहेज करने लगे हैं। किसी ने पहले योजना बनाई थी तो उसे रद्द तक कर दिया। अब भारत में ही शादी करेंगे, यह भावना बढ़ रही है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में भारत का भविष्य तय करने वाला है।

स्वदेशी की सुखद अनुभूति

स्वदेशी की ताकत क्या होती है, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं के अनुभव से हाल ही में बताया। बात लगभग 50 वर्ष पहले की है। तब वे कुछ समय के लिए कन्याकुमारी में रहते थे। उनके कंधे पर हमेशा गमछा रहता था। उनके थैले में भी तीन-चार

खादी

लोकल से ग्लोबल हुई भारत की खादी

[illegible]

- पिछले 11 वर्षों में कारीगरों के वेतन में 275% की वृद्धि हुई है। पिछले वित्त वर्ष में ही इसमें 20% की वृद्धि हुई है।

खादी के उत्पादन एवं बिक्री का आंकड़ा बढ़ा

- वित्त वर्ष 2013-14 में खादी उत्पादों का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, जो 366% बढ़ कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,783.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- खादी उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 1,081.04 करोड़ रुपये थी, वह वित्त वर्ष 2024-25 में 561% वृद्धि के साथ करीब 7,145.61 करोड़ रुपये पहुंच गई।

भारतीय-वैश्विक बाजार में ऐसे बढ़ी साख

- राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट) के साथ मिलकर नई डिजाइनों में आधुनिकता लाने की व्यवस्था।
- Gem.gov.in और khadiindia.gov.in के माध्यम से ई-मार्केटिंग के लिए ई-पोर्टल विकसित कर उत्पादों की आपूर्ति और मार्केटिंग की व्यवस्था की गई है।
- खादी प्रेमियों और डिजाइनरों के लिए विभिन्न शहरों में खादी फैशन शो की शुरुआत की गई है।
- वैश्विक स्तर पर खादी ब्रांड संरक्षित करने के लिए ट्रेडमार्क 'खादी' और 'खादी भारत' लोगो के लिए विभिन्न देशों में पंजीकरण प्राप्त करना।

खादी और ग्रामोद्योग विभाग हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 25 अक्टूबर तक पूरे देश में खादी महोत्सव का आयोजन कर रहा है।

गमछा रखते ही थे। एक बार वे गमछा डाले कन्याकुमारी में घूम रहे थे। तभी कुछ लोग दौड़कर उनके पास आए और अभिवादन करते हुए पूछ लिया- क्या आप असम से हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं गुजरात से हूं। तब लोगों ने कहा कि हमने गमछा देखा, इसलिए लगा कि आप असम से होंगे। यह ताकत है स्वदेशी की, पहचान है स्वदेशी की। भारत के किसी भी प्रदेश में बना उत्पाद आज एक पहचान बन रहा है। इसी को बीते एक दशक से नई दिशा मिल रही है और लोग गर्व से स्वदेशी के प्रति प्रेरित हो भी रहे हैं और दूसरों को कर भी रहे हैं।

स्वदेशी की ताकत क्या होती है? इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण केवल देश ने ही नहीं, बल्कि दुनिया ने इस दिवाली से पहले देखा है। भारत की सैन्य शक्ति और उसमें स्वदेशी की भूमिका ने भारत की साख और बढ़ाई है। पहलगाम में 26 निर्दोषों की नृशंस हत्या के बाद भारत ने आतंकवादियों के समूल नाश का बीड़ा उठा लिया। इसी वर्ष 6-7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर निर्णायक प्रहार किया। इस ऑपरेशन

खिलौना

खिलखिलाया हमारा खिलौना उद्योग

खिलौना उद्योग में स्वदेशी को बढ़ावा देने और उत्पादन तक करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अगस्त 2020 में 'मन की बात' कार्यक्रम में बात की थी। जिसका असर खिलौना क्षेत्र में दिख रहा है। कभी आयात पर निर्भर रहने वाले भारत का खिलौना उद्योग आज घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से न सिर्फ बढ़ा है बल्कि 153 देशों को खिलौने का एक्सपोर्ट कर रहा है निर्यात...

पहल जिनसे देश में खिलखिला रहा खिलौना उद्योग...

52% घटा आयात

वर्ष	आयात
2014-15	332.55
2022-23	158.66

239% बढ़ा निर्यात

वर्ष	निर्यात
2014-15	96.17
2022-23	325.72

- 1 जनवरी, 2021 से भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य किया गया। इसके बिना ऐसे खिलौनों का निर्माण, बिक्री, आयात व वितरण प्रतिबंधित है।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने घरेलू खिलौना मैन्युफैक्चरिंग को 1407 यूनिट जबकि विदेशी खिलौना मैन्युफैक्चरिंग की 40 यूनिट को लाइसेंस दिए हैं।
- राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना और द टॉयकाथॉन 2021 जैसी पहल की गई है।
- आयात किए जाने वाले खिलौनों के नमूना परीक्षण अनिवार्य, गुणवत्ता में फेल होने पर बिक्री की अनुमति नहीं।
- 14 खिलौना क्लस्टर को दी गई है मंजूरी, इससे 7 राज्य के करीब 11 हजार कारीगर जुड़े हैं।
- केंद्र सरकार अब खिलौना क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना लाने पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने टॉयकाथॉन शुरू किया तो इस क्षेत्र में **100%** विदेशी निवेश की मंजूरी भी दी।

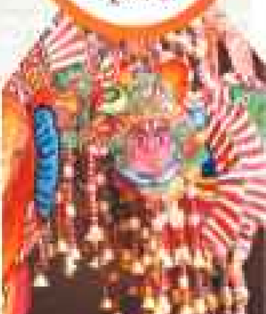

के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सिद्ध किया है। विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलें, जिनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि आज पाकिस्तान में बच्चों तक को ब्रह्मोस की आहट आ जाए तो वहां नींद नहीं आती।

स्वदेशी की ताकत क्या होती है इसे कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों में भारत ने कर दिखाया था। आपदा जैसे अवसर बनाती है, यह चुनौतीपूर्ण कालखंड इसका उदाहरण है। पहले की स्थिति होती तो कोविड वैक्सीन भारत आते-आते 4-5 दशक निकल जाते। लेकिन भारत ने संकल्प लिया और स्वदेशी वैक्सीन बना ली और उसे 140 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा भी दिया। यह सामर्थ्य है नए भारत का। इसी सामर्थ्य और विश्वास से नया भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आज देश का नागरिक यह समझ रहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत है। यही कारण है कि आज

फार्मा

200 से ज्यादा देशों की विश्वसनीय फार्मेसी के रूप में उभरा भारत

भारत की फार्मा इंडस्ट्री का न सिर्फ तेज गति से विस्तार हो रहा है बल्कि विश्व समुदाय का भरोसा भी बढ़ा है। वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान मात्रा के हिसाब से तीसरा और मूल्य के हिसाब से 14वां है। यह विश्व की 20% जेनेरिक दवाओं और 60 फीसदी से अधिक वैक्सीन की जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया भर में किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। उत्पादन, निर्यात और घरेलू अवसर में लगातार वृद्धि के साथ विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को दिखाते और आंकड़े...

10,400
करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की जा चुकी है जिसमें 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात भी शामिल है। मार्च, 2025 तक पीएलआई के अंतर्गत।

भारत के निर्यात में हिस्सेदारी

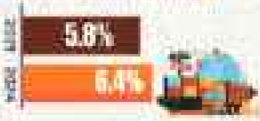

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत दवाओं के कच्चे माल (एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स(एपीआई)) का आयातक से वर्ष 2024-25 में 2,280 करोड़ रुपये का निर्यातक बन गया।

- नैफिथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक, फार्मा इनोवेशन में मील का पत्थर।
- लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डायलिसिस मशीन, सी-आर्म और एमआरआई कॉइल के लिए पहली बार भारत में निर्माण। पीएलआई योजना की 21 परियोजनाओं के तहत इन उपकरणों के साथ ही कैथलैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, हार्ट वाल्व, स्टेंट और इम्प्लांट सहित 54 विशिष्ट उपकरणों का भी उत्पादन शुरू हो चुका है।
- औषधि पीएलआई में 6 साल के लिए कुल 15 हजार करोड़ रुपये रखा गया। जून 2025 तक लक्ष्य से ज्यादा [illegible] करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है।
- [illegible] करोड़ रुपये के उत्पादों की बिक्री की जा चुकी है, जिसमें [illegible] करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।
- यूनिक इंटरमीडिएट सामग्री और थोक दवाएं अब भारत में निर्मित हो रही हैं, जिसमें पेनिसिलिन जी भी शामिल है।

3,420
करोड़ रु. प्रोत्साहन का लक्ष्य है मेडिकल उपकरण और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में पीएलआई के तहत।

पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है।

आज खादी से खिलौने तक, रक्षा से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, मोदी सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनसे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रख दी है। आज सुई से लेकर सेना के साजो-सामान तक, साइकिल से लेकर वाहन तक, मोबाइल से लेकर कार तक, घरेलू उत्पाद से लेकर मेडिकल डिवाइस तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। जिसमें अपनों का पसीना है और अपने देश की महक है। देश के उज्ज्वल भविष्य के इन्हीं सपनों को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है।

आत्मनिर्भरता का उत्सव

यह त्योहारों का मौसम है। हाल ही में नवरात्रि, विजयदशमी का त्योहार देश ने मनाया है तो अब धनतेरस, दीपावली, छठ और अन्य त्योहार मनाया जा रहा है। यह केवल भारत की संस्कृति के उत्सव नहीं है, बल्कि बीते एक दशक से यह

अंतरिक्ष

स्वदेशी की सोच से आत्मनिर्भरता

अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक अहम मोड़ 2014 में प्रमुख अंतरिक्ष सुधारों की शुरुआत के साथ आया। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलने के साथ कई वैश्विक सहयोगों ने भारत की लंबी छलांग के लिए मंच तैयार किया...

एक्सिओम मिशन-4 के साथ भारत के **ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला** अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने।

- जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक इसरो ने वाणिज्यिक आधार पर कुल 393 विदेशी उपग्रह और 3 भारतीय ग्राहक उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें 34 देशों के उपग्रह शामिल हैं।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक दशक में चंद्रमा तक पहुंच कर भारत ने नया इतिहास रचा तो चंद्रयान-3 के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना।
- निसार अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- 16 जनवरी 2025 को भारत निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला चौथा देश बन गया।
- 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल-1 के साथ भारत ने अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया था।
- गगनयान कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में भेजने का लक्ष्य तय किया गया है।
- 2023 में अंतरिक्ष नीति के जरिए भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किए गए। 300 स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
- वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की स्थापना और 2040 तक भारतीय यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना भारत के लक्ष्य में शामिल है।

100% तक विदेशी निवेश और इन-स्पेस जैसी पहलों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयां दीं।

आत्मनिर्भरता का उत्सव बन रहा है। इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। जनमानस इसके लिए तैयार हो रहा है लेकिन इसे आजीवन संकल्प बनाने की जरूरत है। जीवन का संकल्प और मंत्र हो इस बात का कि हम जो भी खरीदेंगे, वह मेड इन इंडिया होगा। स्वदेशी होगा। घर की साज-सज्जा का सामान हो या दोस्तों को उपहार देना, वह भारत में बना हो। दुकानदारों-व्यापारियों को भी अपनी दुकान में स्वदेशी उत्पाद रखना चाहिए। दुकान पर बोर्ड लगाना चाहिए कि यहां केवल स्वदेशी उत्पाद मिलता है। ऐसे छोटे-छोटे प्रयास ही भारत के प्रत्येक उत्सव को समृद्धि का महोत्सव बनाएंगे। अगर देश का जन-जन संकल्प कर ले, उस संकल्प के प्रति श्रद्धा हो, समर्पण हो तो देश को आत्मनिर्भर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हर देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल का वाहक बनेगा, स्वदेशी के मंत्र को जियेगा तो कभी भी हासिल करने का अवसर नहीं आएगा।

टेलीकॉम

आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात का वैश्विक केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के लिए वर्ष 2014 तक आयात पर निर्भर भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। आंकड़ों को समझिए कैसे पिछले ग्यारह वर्षों में ... इस क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने की कहानी...

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग

(एक दशक में 6 गुना की बढ़ोतरी)

- मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या 2014-15 में 2 से बढ़कर 2024-25 में 300 हो गई।
- मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये का हो गया। 28 गुना बढ़ोतरी।
- मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया, जो 127 गुना वृद्धि है।
- मोबाइल फोन का आयात 2014-15 में कुल मांग के 75 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में मात्र 0.02 प्रतिशत रह गया, जो कि लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरता की स्थिति को दर्शाता है।

स्मार्टफोन आज भारत से निर्यात होने वाला तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात

(एक दशक में 8 गुना की बढ़ोतरी)

> विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए, हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें, वो स्वदेशी हो। हम जो भी बेचें, वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं, जिसमें लिखा हो- गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। हमारा ये प्रयास हमारे हर उत्सव को भारत की समृद्धि का महोत्सव बना देगा।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वदेशी चाबी जो बना दे हिंदुस्तान को

स्वदेशी चाबी जो खोले देश में बनी हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी के लिए अपने आह्वान को दोहराया तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान पीढ़ी से त्याग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "दोस्तो, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे भारत के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे यही कहता हूं कि आज मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा।

स्वच्छ ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति का दशक

जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच स्वच्छ ऊर्जा भारत और दुनिया की राह दिखा रहा है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भारत ने 5 साल पहले पूरा करने वाला पहला देश बन गया।

17.24 लाख परिवार अब तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

9,842 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2.24 लाख यूनिट के साथ यूटिलिटी स्केल और घरों की बिजली रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची।
- अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत आज दुनिया में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे, सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है।
- 500 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य की ओर 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 गुना बढ़ चुकी है। गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट पहुंच चुकी है।
- भारत विकास और डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में अपना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विस्तार कर रहा है। भारत न्यूक्लियर ऊर्जा पर भी काम कर रहा है।
- इस क्षेत्र में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक देश परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले 11 वर्षों में सौर विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर **11.59** गीगावाट हो गई है।

भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों का 100 देशों में शुरू हुआ निर्यात

स्वदेशी खरीदेंगे। मेड इन इंडिया खरीदेंगे और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सहज है। कंपनी किसी भी देश से क्यों न आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों न हो, लेकिन जो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। जो भी मेड इन इंडिया होगा, उसमें मेरे भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। अपने गाँव की हर दुकान पर बोर्ड लगाइए गर्व से कहो ये स्वदेशी है। स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा बन गई है। आज प्रत्येक भारतीय 'वोकल फॉर लोकल' का ब्रांड एंबेसडर बन रहा है। स्वदेशी चीजों पर गर्व कर रहा है। स्वदेशी ही खरीदना और स्वदेशी ही बेचना, गर्व की अनुभूति करा रहा है, क्योंकि इन अभियानों को नागरिकों के प्रयासों से जितनी गति मिलेगी, विकसित भारत का सपना उतनी ही तेज गति से पूरा होगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स से भी प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि सामान की गुणवत्ता उत्कृष्ट बनाएं, कीमतें प्रतिस्पर्धी रखें, ताकि लोग अधिक से अधिक भारतीय सामान खरीदने के लिए प्रेरित हों।

निर्यात

रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारत का निर्यात

उद्योगों को समर्थन और अनुकूल नीतियों के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम देश के निर्यात क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। [illegible] 2024-25 में कुल निर्यात [illegible] 6 फीसदी की बढ़ोतरी है, [illegible] 7 फीसदी ज्यादा की वृद्धि।

निर्यात में 38% की वृद्धि

2013-14	$310 बिलियन
2024-25	$437.42 बिलियन

- भारत से अब मेट्रो कोच ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए जा रहे हैं।
- [illegible] मैक्सिको, [illegible] स्पेन, जर्मनी और इटली को निर्यात किए गए।
- भारत से फुटबॉल, चूड़ी, [illegible] और [illegible] इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- 2024-25 में, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर वस्तु (मर्चेंडाइज) निर्यात 374.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2023-24 के 352.9 अरब डॉलर की तुलना में 6.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यह अब तक का सबसे अधिक गैर-पेट्रोलियम वस्तु निर्यात है।

एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, हथियारों और विद्युत मशीनरी के निर्यात में 2014 के बाद करीब 200 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

374.1 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा भारत का गैर-पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में।

छात्र जीवन से ही स्वदेशी बने जीवनशैली

मन की बात का पहला कार्यक्रम हो या फिर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में वोकल फॉर लोकल का आह्वान, आज आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्कूलों में भी बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए, जिसका विषय 'मेक इन इंडिया' हो। कुछ देर के लिए अपने क्षेत्र में स्वदेशी का जुलूस निकालें। स्कूलों में इसके लिए उत्सव मनाएं। स्वदेशी दिवस, स्वदेशी सप्ताह, स्थानीय उत्पाद दिवस मनाएं। बच्चे अपने घरों में स्वदेशी सामान की सूची बनाकर स्कूल में लाएं, हर महीने यह काम करें कि स्वदेशी सामान की संख्या घर में बढ़ाएं। स्वदेशी के महत्व पर परिचर्चा का आयोजन हो। बच्चों के जन्मदिन पर स्वदेशी उपहार देने की थीम बनाएं। इसका परिणाम होगा कि बचपन से ही स्वदेशी की भावना बढ़ेगी और धीरे-धीरे पूरा परिवार स्वदेशी हो जाएगा। ऐसा करने से 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का अपना [illegible] में सिद्ध होगा।

भारत के लिए आत्मनिर्भरता, नया कोई नारा नहीं है। इस

नीति और नीयत

पहल... जो बनी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सपने की नींव

[illegible]

कारोबारी सुगमता

[illegible]

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन ने मोबाइल, रक्षा, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताओं के साथ भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

118 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 2014 में केवल 4 थे। (1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप)

स्टार्टअप इंडिया : युवा उद्यमियों पर भरोसा

भारत पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स के एक छोटे समूह से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह वृद्धि उद्यमशीलता की भावना, डिजिटल के विस्तार और सक्रिय सरकारी समर्थन से प्रेरित रही है।

17 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए, करीब 2 लाख स्टार्टअप के जरिए

कर सुधार

[illegible]

- केंद्र और राज्य सरकारों में 45 हजार अनुपालन बोझ समाप्त किए गए।
- कंपनी अधिनियम के तहत 63 समझौता योग्य अपराधों में से 39 का गैर-अपराधीकरण।
- जन विश्वास अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन - 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया।

1,500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

भारत के सुधारों ने न केवल घरेलू कारोबारी माहौल को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी आकर्षक बनाया है। [illegible] के क्षेत्र में उठाए गए कदमों ने अनुपालन का बोझ कम किया, कारोबार को सहज बनाया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयासों की शुरुआत की।

भारत की रैंकिंग

142	63
2014	2019

(वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट)

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जो अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता में मजबूत प्रगति को दर्शाता है।

भारत में दिए गए पेटेंट 2014-15 में 5,978 से बढ़कर 2023-24 में 1,03,057 हो गए हैं, जो नवाचार उत्पादन में 17 गुना वृद्धि दर्शाता है।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

पीएलआई योजना [illegible] जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25 तक बढ़ाने और दुनिया की अग्रणी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रही है।

1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 14 रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करती है।

मार्च 2025 तक [illegible] रुपये का निवेश किया गया है।

16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और बिक्री हुई।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से [illegible] से अधिक रोजगार सृजित हुए।

दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण शुरुआत से ही हो। बच्चों को बहुत सरलता से, उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, आप कल्पना कीजिए, देश में आज भी एक लाख करोड़ रुपये का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। अगर इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाया गया होता तो अभी जो एक लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो नहीं जाता। उससे कितने स्कूलों की बिल्डिंग बनती। कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती और इसलिए, आत्मनिर्भर भारत की बात को जीवन का मंत्र बनाना पड़ेगा और नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा।

स्वदेशी: आजादी से पूर्व और अब

स्वदेशी आंदोलन भारत की आजादी के प्रमुख आंदोलनों में से एक है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारतीयों ने सरकारी सेवा, स्कूल, न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। [illegible] यह राजनीतिक आंदोलन के

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन

भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र मौजूदा वक्त में आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतीक बन चुका है। इस रुझान को और तेज करने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता को बढ़ावा देना है।

मिशन सेमीकंडक्टर

76,000

करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में इस मिशन की शुरुआत की है।

इस वर्ष के अंत तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी।

अभी तक 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें कुल मिलाकर करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश 6 राज्यों में हो रहा है।

पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप

भारत ने अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम-32-बिट माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया।

एमएसएमई पर खास फोकस

अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का खास फोकस है। परिवर्तनकारी सरकारी योजनाएं जैसे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना और सार्वजनिक खरीद नीति ने प्राथमिकता से क्षेत्र को लगातार मजबूत बनाया है।

> आज जब हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो देश की हमसे भी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा है- आत्मनिर्भरता की। भारत विकसित तभी होगा, जब भारत आत्मनिर्भर होगा। और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है- स्वदेशी का मंत्र। आज समय और देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं। खरीदें वही, जो देश में बना हो, बेचें वही, जो देश में बना हो, गर्व से कहें- ये स्वदेशी है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

खास-खास क्षेत्रों पर आर्थिक चोट करने वाला आंदोलन भी था। आंदोलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1905-08 के दौरान विदेशी सामानों की खरीद में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। इससे देश में स्वदेशी कपड़ा मिल, साबुन और माचिस की फैक्ट्री, चर्मशोधन कारखाना, बैंक और बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। इसने पारंपरिक कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित किया।

अब 2014 से 'वोकल फॉर लोकल' की मुहिम से लेकर कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र ने ऐसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रत्येक अवसर और विशेष रूप से त्योहारों के मौके पर किया जाने वाला आह्वान भारत को विकसित बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन शुरू किया, यह दिवस पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया। इस तिथि का चयन विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन की याद में किया गया था। आजादी की लड़ाई के समय जैसे खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश, विकसित भारत बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। आज भारत में 3,000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप ने भारत के

जीएसटी

नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार से स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा

स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों का अनुपालन बोझ कम करने के साथ घरेलू विनिर्माण की समृद्धि के लिए पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई पहल की है, जिसमें नई पीढ़ी का जीएसटी सुधार एक महत्वपूर्ण कदम बना है। [illegible] लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को बढ़ावा देना है [illegible] आत्मनिर्भर [illegible] प्रतिस्पर्धी और [illegible] आगे बढ़ाने में [illegible]...

2,500 रु. तक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी **5%** किए जाने से टियर 2 और टियर 3 शहरों में मांग बढ़ेगी।

खाद्य उत्पादों पर जीएसटी घटाकर **5%** किए जाने से फूड प्रोसेसिंग के एमएसएमई को लाभ होगा।

- जीएसटी दरों में कटौती से पीएलआई योजनाओं के तहत [illegible] और [illegible] विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू उत्पाद आयात के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।

वाहनों पर जीएसटी कम किए जाने से ऑटो कंपोनेंट जैसे टायर, बैटरी, ग्लास, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के एमएसएमई को लाभ मिलेगा।

- अधिकांश खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, लघु उत्पादकों, डेयरी सहकारी समितियों, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी एमएसएमई को प्रोत्साहन।
- हस्तशिल्प पर जीएसटी 5% किए जाने से भारतीय [illegible] सस्ती होगी तो वहीं दूसरे देशों के उत्पादों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में भी बेहतर स्थिति होगी।
- खिलौने और खेल के सामान पर कम जीएसटी से वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा, आयात पर निर्भरता कम होगी।

मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी 5% करने के साथ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही किए जाने से एमएसएमई वस्त्र निर्माताओं को लाभ होगा।

हस्तकरघा को वैश्विक ऊंचाई दी है। किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण में जन-जन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यही सोच 2014 से समाज के सभी वर्गों को देश के संसाधनों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई दीर्घकालिक योजनाएं लेकर आई। इसमें वोकल फॉर लोकल अभियान ने दशकों तक सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय तक के जीवन और उत्पादों को नई ऊंचाई दी। इन्हीं प्रयासों को एक पहचान 2020 में मिली, जब ऑक्सफोर्ड हिन्दी ने आत्मनिर्भरता को साल का हिंदी शब्द चुना।

आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए समृद्ध भारत। अगर कोटि-कोटि लोगों के बलिदान से भारत स्वतंत्र हो सकता है, तो कोटि-कोटि लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध भारत भी बन सकता है। आइए, हम सभी मिलकर 'वोकल फॉर लोकल', स्वदेशी के मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं।

स्वदेशी तकनीक की शुरुआत का साक्षी बना ओडिशा

आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए बीएसएनएल ने पूरी तरह से स्वदेशी 4जी तकनीक विकसित की है, जिससे भारत 4जी सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक वाले दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल हो गया है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में इस तकनीक की शुरुआत सहित 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी राष्ट्र के साथ राज्य के विकास को गति...

भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की 25वीं वर्षगांठ (27 सितंबर) एक नया इतिहास रच गया। इस दिन भारत में स्वदेशी 4जी नेटवर्क की शुरुआत न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना है, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी 4जी तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल होकर एक वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से इसे लॉन्च किया। स्वदेशी तकनीक के 4जी टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इससे देश भर में दो करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ होगा। 30 हजार से अधिक गांव हाई-स्पीड इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाएंगे।

इस स्वदेशी तकनीक की शुरुआत ओडिशा के झारसुगुड़ा से करना भी एक नई प्रतिबद्धता के साथ विकसित ओडिशा की ओर बढ़ने की संकल्प शक्ति का परिचायक बना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी, "आज केंद्र और राज्य में उनकी सरकारों की नीति के साथ ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है।" इस अवसर पर ओडिशा और राष्ट्र के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई। ओडिशा में आईआईटी का विस्तार, शिक्षा, कौशल विकास और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाएं, बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी और अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ओडिशा के लिए मंजूर दो सेमीकंडक्टर इकाइयों और एक सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना का जिक्र करते हुए बताया कि भविष्य में फोन, टेलीविजन, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार और कई अन्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली छोटी चिप ओडिशा

BSNL

ओडिशा के झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास आदि क्षेत्रों की 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन...

- दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, स्वदेशी तकनीक से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण।
- इनमें बीएसएनएल द्वारा स्थापित 92,600 से अधिक 4G तकनीकी साइटें शामिल हैं।
- नए टावर, दीवारों और चहारदीवारी तक प्रभावित होंगे। लगभग 26,700 असंबद्ध गांवों को जोड़ेंगे और 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगे।
- ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे ये भारत के सबसे बड़े ग्रीन दूरसंचार टावरों का समूह बन गए हैं।
- संबलपुर-सरला में रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट-बैगुडा लाइन के दोहरीकरण और मनाबार-कोरापुट-गोरापुर लाइन राष्ट्र को समर्पित।
- बरहमपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी।
- लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 8 आईआईटी- तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर के विस्तार की आधारशिला रखी गई।
- इस विस्तार से अगले चार वर्षों में 10 हजार नए छात्रों के लिए क्षमता का सृजन होगा तथा अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं स्थापित होंगी।
- देश भर के 275 राज्यस्तरीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता, समानता, अनुसंधान और शासन में सुधार के लिए मेरिट (MERITE) योजना का शुभारंभ।
- ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण का अनावरण, जिसके तहत संबलपुर और बरहमपुर में विश्व कौशल केंद्र स्थापित होंगे। इसके अलावा, 5 आईटीआई को उत्कृष्ट आईटीआई में उन्नत किया जाएगा, 25 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा तथा नए डिजिटल इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाई-फाई सुविधाएं समर्पित, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिदिन मुफ्त डेटा सुविधा मिलेगी।
- बरहमपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संबलपुर स्थित वीआईएमएसएआर को विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला रखी गई।
- अंत्योदय गृह योजना के तहत 50 हजार लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किया गया।

> हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4जी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। नया इतिहास रच दिया है। हम उन देशों की सूची में आ गए हैं, जिनके पास 4जी सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। भारत पहले ही सबसे तेज 5G रोलआउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये टावर बहुत आसानी से 5जी सेवा के लिए भी तैयार हो जाएंगे।
>
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

में ही बनाई जाएंगी। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं और एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने मेरिट (MERITE) नामक एक नई योजना का शुभारंभ भी की। इस योजना के तहत, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

पिछले ग्यारह वर्षों में देश में जो आधुनिक कनेक्टिविटी, राष्ट्र सुविधा और समृद्धि का मार्ग बना रहा। इससे ओडिशा को भी बहुत लाभ मिल रहा है। ओडिशा में आज कई वंदे-भारत ट्रेन चल रही हैं। तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। झारसुगुड़ा का वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा आज देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। खनिज और खनन से अब ओडिशा को पहले से अधिक धन मिल रहा है। सुभद्रा योजना से भी ओडिशा की महिलाओं को निरंतर सहायता मिल रही है। कुल मिलाकर, ओडिशा प्रगति पथ पर अग्रसर हो चुका है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए यह कोड स्कैन करें।

प्रेरणा पीएम मोदी की हर दिवाली देश के जवानों के संग

भारतीय सेना के पराक्रम का
दीपोत्सव

अपनी हर दिवाली देश के जवानों के संग मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह दिवाली विशेष अवसर बनकर आई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के रणबांकुरों ने इसी वर्ष अपना पराक्रम देश-दुनिया को दिखाया है। उसके बाद की यह पहली दिवाली है। बीते 7 अक्टूबर को लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सदैव राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उनका मानना है- जहां देश के सुरक्षाबल तैनात हैं, मेरे लिए वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। इसलिए वे गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर बतौर प्रधानमंत्री की यात्रा में अपना हर दीपोत्सव देश के जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं...

इस दीपावली का विशेष महत्व है। यह भारतीय सेना के पराक्रम का दीपोत्सव है। यह युद्ध की बदलती प्रकृति में भारत के सामर्थ्य के उद्घोष का दीपोत्सव है। पिछली दिवाली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के संग दीपावली मनाई थी, तभी उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति का जिक्र किया था। लेकिन, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगली दिवाली से पहले भारत के इस नए रूप का दुनिया साक्षात दर्शन करेगी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के नए युग की युद्ध रणनीति का परिचायक बन गया है। गुजरात के कच्छ में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "आज जब न्यू एज वारफेयर की बात होती है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका अहम उपकरण बन रही है। हम देख रहे हैं कि युद्ध में शामिल देश आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है। ड्रोन से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। किसी व्यक्ति या जगह की पहचान करने में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ड्रोन सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए भी चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सेनाओं को, अपने सुरक्षाबलों को सशक्त कर रहा है।"

ऑपरेशन सिंदूर की निर्णायक सफलता, प्रधानमंत्री मोदी की उसी दूरदृष्टि का द्योतक बन गई है। राष्ट्र प्रथम की सोच से समर्पित उनका जीवन देश और समाज के लिए प्रेरणा है। वे सांगठनिक सफलता और राष्ट्र को नई उपलब्धियों पर ले जाने वाली एक प्रेरणा बन गए हैं। शायद यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का लक्ष्य क्या

हर काम देश के नाम...

भारतीय सेना के साथ प्रधानमंत्री की दीपावली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद कहां और कैसे मनाई दीपावली, आइए जानते हैं एक नजर...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दीवाली मनाई। उन्होंने जवानों को मिठाई भी खिलाई और आस-पास के इलाकों के लोगों से भी बातचीत की।

जम्मू-कश्मीर के गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के निकट सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 की दीवाली मनाई।

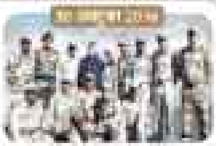

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत-चीन सीमा के निकट सुमदो में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना, आईटीबीपी के जवानों और डोगरा स्काउट्स के साथ दीवाली मनाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में पंजाब में 1965 के युद्ध स्मारकों का दौरा किया और सेना के अफसरों और जवानों के साथ दीवाली मनाई।

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने 12 हजार फुट की ऊंचाई पर सियाचिन के बेस कैंप में सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों के साथ दीवाली मनाई।

> सभी की तरह मैं भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की इच्छा रखता हूं। इसलिए आपके बीच (सुरक्षा बलों के जवानों) आता हूं, क्योंकि आपको ही अपना परिवार मानता हूं। आपके बीच आकर समय बिताता हूं तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इच्छा शक्ति, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, जब देश देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब भारत की सेना की ओर देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मन जब देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। सेना के जवान जब जोश से दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं।

सेना के संकल्पों से बन रही रक्षा नीतियां

आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के एक इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। देश की नीतियां सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती हैं। देश आज दुश्मन की बातों पर नहीं, बल्कि सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करता है। आज 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए, सुरक्षाबलों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। भारतीय सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा किया जा रहा है। इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी, आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। सेना ने 5 हजार से अधिक ऐसे सैन्य उपकरणों की सूची बनाई है, जिन्हें अब विदेश से नहीं खरीदा जाता है। इससे सैन्य स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिली है। सीमावर्ती क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत का आधुनिक बनाया जा रहा है। सीमावर्ती गांवों को, आखिरी गांव मानने की सोच भी बदली है। अब उन्हें देश का प्रथम गांव मानते हैं।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से योजनाओं-नीतियों को नया रूप दिया है तो त्योहारों को भी नया प्रतिमान बना दिया है। हर दिवाली देश के जवानों के संग मनाना एक प्रेरणा बन गया है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकता है, इसलिए आज जब विकसित भारत के लक्ष्य की ओर राष्ट्र तेजी से बढ़ रहा है तो हमारी भारतीय सेना इस सपने के रक्षक बनकर खड़ी है।■

उद्योग और अवसरों का संगम

देश की सबसे बड़ी आबादी और तेजी से विकसित होते बुनियादी ढांचे के साथ उत्तर प्रदेश अब न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि एक उभरते हुए औद्योगिक शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी यहां व्यापार और व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी तय किया है...और इस दिशा में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो-2025 साबित होगा मील का पत्थर...

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में असाधारण निवेश संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अब देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यहीं हैं। धार्मिक पर्यटन में भी पहले स्थान पर है। नमामि गंगे जैसी पहलों ने राज्य को क्रूज पर्यटन के मानचित्र पर भी लाकर खड़ा किया है। पिछले एक दशक में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है जो देश में निर्मित मोबाइल फोन का लगभग 55 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। यहीं नहीं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी यह प्रदेश भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान कर रहा है। इन उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी हितधारकों से यहां निवेश और निर्माण करने का आह्वान किया, जहां एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क है।

वर्ष 2023 में शुरू हुए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसका विषय 'मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है' रखा गया। इस शो के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य थे—नवाचार, एकीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण। इस बात के प्रमाण शो में भी साफ दिखाई देते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर और ओएनडीसी नेटवर्क जैसे डिजिटल सार्वजनिक ढांचे तैयार किए हैं जो सभी को समान अवसर देते हैं। इसका लाभ यह हुआ है कि गांव में सब्जी बेचने वाले तक, यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। औपचारिक ऋण जो कभी केवल बड़ी कंपनियों के लिए सुलभ था वो अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों तक आसानी से पहुंच रहा है।

हर उत्पाद पर हो 'मेड इन इंडिया' की छाप

देश में एक ऐसा जीवंत नया क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां हर उत्पाद पर मेड इन इंडिया की छाप हो। नव के महाकौशल से स्थापित एक उत्पादन में जल्द ही करीब 300 ... का निर्माण भी शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में एक रक्षा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल और ... हथियार प्रणालियों का निर्माण शुरू हो चुका है।

सभी को मिला एक मंच

- इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में राज्य की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, उभरते एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को एक मंच पर आने का मौका मिला। इसमें हस्तशिल्प, कपड़ा, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष जैसे क्षेत्र शामिल रहे। इसके अलावा प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी इस मंच पर प्रदर्शित किया गया।

व्यापार मेले में करीब
2,400 प्रदर्शक

1.25 लाख से ज्यादा बीटूबी आगंतुक और 4.5 लाख से ज्यादा बीटूसी आगंतुकों ने भाग लिया।

> आज हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो... हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं।
>
> -नरेंद्र मोदी
> प्रधानमंत्री

एक समय था जब सरकार को केवल बड़े व्यापारी ही सामान बेचते थे लेकिन आज सरकार की नीतियों की वजह से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता जुड़े हुए हैं। इनमें छोटे व्यापारी, कारीगर और दुकानदार भी शामिल हैं जो अब सीधे भारत सरकार को सामान बेच सकते हैं। अब तक जेम के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा चुकी है। इसमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा छोटे व्यापारी से की गई है। सरकार की इस पहल का फायदा यह हुआ कि अब देश के सुदूर कोने में बैठा एक छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहा है, यही अंत्योदय का सार और भारत के विकास मॉडल का आधार है।

सरकार की ऐसी कई पहल हैं जिनकी वजह से वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। व्यवधान भारत को भटकाते नहीं हैं बल्कि नई दिशा प्रदान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों पर निर्भरता से बड़ी कोई लाचारी नहीं है। बदलती दुनिया में, कोई देश जितना अधिक दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि उतनी ही प्रभावित होती है। ऐसे में भारत में निर्मित किए जा सकने वाले हर उत्पाद का निर्माण भारत में ही होना चाहिए। व्यापार मेले में आए उद्यमियों, व्यापारियों और हितधारकों से पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसा व्यावसायिक मॉडल तैयार करें जो भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करे।

व्यापार और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए ही पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने 40 हजार से ज्यादा अनुपालन और नियमों को समाप्त किया है। सैकड़ों ऐसे नियम जो पहले छोटी-मोटी व्यावसायिक गलतियों के कारण अपराध की श्रेणी में आते थे, उन्हें अपराधमुक्त किया गया है। सरकार सब उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी आग्रह किया कि देश निर्मित सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के होने चाहिए, गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।■

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन देखने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें

आम आदमी की ऊंची उड़ान

"एक आम आदमी जो हवाई चप्पल पहनकर यात्रा करता है, वह भी विमान में दिखे। यह मेरा सपना है।"

'उड़े देश का आम नागरिक' यानी उड़ान योजना की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से शुरू होती है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई यात्रा को सर्व सुलभ बनाने की आवश्यकता को लेकर अपना विजन इन्हीं शब्दों के साथ नीति निर्माताओं के सामने रखा था। आम आदमी के साथ छोटे शहरों तक हवाई सेवा की पहुंच बनाने की इस प्रतिबद्धता ने 21 अक्टूबर 2016 को आकार लेना शुरू किया। उड़ान योजना की 9वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता से उड़ान की सफलता तक के सफर पर एक नजर...

आकाश को हमेशा से आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक माना गया है। लेकिन, हवाई जहाज की यात्रा लंबे समय तक आमजन के लिए सिर्फ एक सपना और अभिजात वर्ग के लिए विलासिता का प्रतीक बनी रही। आम आदमी और हवाई यात्रा के बीच बनी दूरी को खत्म करने के लिए वर्ष 2016 में बनी देश की पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत 10 साल के दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य था, कम कीमतों पर हवाई यात्रा टिकट आम आदमी को उपलब्ध कराना और उन शहरों तक हवाई सेवा पहुंचाना, जहां अब तक यह या तो नहीं पहुंची थी या बहुत सीमित रूप में मौजूद थी। 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से नई दिल्ली के लिए उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उड़ान योजना के तहत अभी तक देशभर में 15 हेलीपोर्ट, 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों के 637 मार्गों पर सेवा की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 16 एयरलाइन अपनी सेवाएं दे रही हैं। योजना की शुरुआत से अप्रैल, 2025 तक 3.1 लाख से अधिक उड़ानें परिचालित की जा चुकी हैं। विमानन क्षेत्र में निरंतर सुधार

उड़ान : प्रारंभ से विस्तार तक

2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, उड़ान योजना छह चरणों से गुजरी है, प्रत्येक चरण ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार किया है। [illegible]

उड़ान 1.0 (2017)

शुरुआत: पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को (शिमला-दिल्ली) रवाना हुई।

[illegible]

उड़ान 2.0 (2018)

73 कम सुविधा वाले और बिना सुविधा वाले हवाई अड्डों को शामिल किया गया।

पहली बार हेलीपैड को भी उड़ान नेटवर्क से जोड़ा गया।

उड़ान 3.0 (2019)

पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मार्ग शुरू किए गए।

वाटर एयरोड्रम को जोड़ने के लिए समुद्री विमान परिचालन को शामिल किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को योजना से जोड़ा गया।

उड़ान 4.0 (2020)

पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवा पर अधिक जोर दिया गया।

नए सुधारों के साथ आत्मनिर्भर-उड़ान के 5वें संस्करण का शुभारंभ

- **उड़ान 5.0 (2023):** श्रेणी 2 (20-80 सीटें) और श्रेणी 3 (80 से ज्यादा सीटें) विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, 600 किलोमीटर की अधिकतम सीमा हटा दी गई। [illegible]
- **उड़ान 5.1 (2023):** इस चरण को विशेषकर हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिजाइन किया गया। [illegible]
- **उड़ान 5.2 (2023):** रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और छोटे विमान के जरिए [illegible] के लिए इस चरण में बोली लगाई गई।
- **उड़ान 5.3 और 5.4 (2024):** इसमें उन मार्गों के लिए बोली मांगी गई जो किसी कारण से [illegible] रद्द कर दिए गए।
- **उड़ान 5.5 (2024):** [illegible]

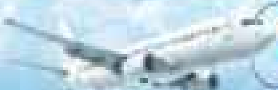

1.50 करोड़ से अधिक आम नागरिक उड़ान योजना की शुरुआत से 31 मार्च, 2025 तक कम खर्च पर हवाई यात्रा का लाभ उठा चुके हैं।

और उड़ान का असर हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के रूप में भी सामने आता है। वर्ष 2014 में जहां हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 11 करोड़ थी, वह 2025 में बढ़कर करीब 25 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित हिंडन हवाई अड्डे से 2020 में केवल एक उड़ान थी, अब यह हवाई अड्डा उड़ान के मार्गों की वजह से देश भर के 16 शहरों से जुड़ गया है। हवाई यात्रियों का अनुभव और अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाने के लिए देश भर में किफायती कैफे जैसी कई पहल की जा रही हैं।

वास्तव में, उड़ान एक नीति से कहीं अधिक है: यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, जिसने भारत में विमानन क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया है। [illegible] इस योजना ने लाखों लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है। इसने न केवल दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला दिया है बल्कि स्थानीय पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है।

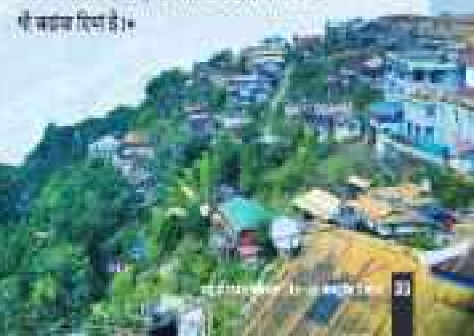

मेडिकल एजुकेशन और मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ेगी भारत की ताकत

बिना देरी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दृष्टिकोण को और मजबूत करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 हजार से अधिक एमबीबीएस और पीजी सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद आने वाले समय में मरीजों के लिए चिकित्सक और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही, जहाज निर्माण और समुद्री इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी...

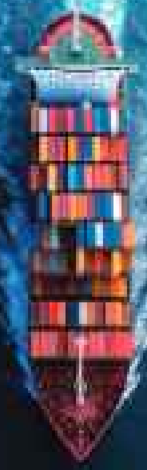

निर्णय : देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता में व्यापक विस्तार को मंजूरी।

प्रभाव : इस निर्णय से वर्ष 2028-2029 तक सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5,000 स्नातकोत्तर और 5,023 स्नातक सीटें बढ़ेंगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपने की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

- सरकारी/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में पीजी और स्नातक सीटें बढ़ने से देश में डॉक्टर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो पाएगी।
- स्नातकोत्तर सीटें बढ़ने से गरीब, वंचितों व पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सक से बिना देरी समय पर इलाज मिल सकेगा।
- मौजूदा बुनियादी ढांचे में लागत-प्रभावी बना रहेगा। स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- आने वाले समय में यह चिकित्सा कौशल और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश की स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएगा।

निर्णय : समुद्री क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी।

प्रभाव : इस व्यापक पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन क्षमता की जहाज निर्माण क्षमता का विकास, लगभग 30 लाख रोजगार सृजन और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

- इस पैकेज के तहत जहाज निर्माण में वित्तीय सहायता को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा। कुल कोष 24,736 करोड़ रुपये होगा। इसका उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। इसकी निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।
- 25,000 करोड़ रुपये समुद्री विकास निधि के लिए मंजूर की गई।
- 19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण विकास योजना को भी मंजूरी।

निर्णय : 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1,865 करोड़ 68 लाख रुपये भुगतान की स्वीकृति।

प्रभाव : यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी।

- वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया।

निर्णय : 2,277.397 करोड़ रुपये खर्च के साथ "कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट" योजना को मंजूरी।

प्रभाव : इस योजना में देश भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल किए जाएंगे।

- इस पहल से विश्वविद्यालयों, उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर बनाने के लिए उत्सुक युवा, उत्साही शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक मंच प्राप्त होगा। प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में इस योजना से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान (एसटीईएमएम) के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह पहल एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास संचालित इनोवेशन इकोसिस्टम के निर्माण और 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय विज्ञान को तैयार करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निर्णय : बिहार में एनएच-139 डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 4-लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

प्रभाव : इस परियोजना की कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर है और इसमें कुल 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

- इस प्रस्तावित चार-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी पटना और बेतिया के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है।
- उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले, भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों तक जुड़ जाएंगे।
- यह परियोजना लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देगी, प्रमुख बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार लाएगी। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों व सीमा पार व्यापार मार्गों से संपर्क में सुधार कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुगम बनाएगी।
- परियोजना से लगभग 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

निर्णय : बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी। इसकी कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है।

प्रभाव : यह परियोजना बिहार राज्य के चार जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

- यह रेल मार्ग राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जो देश भर के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें दो आकांक्षी जिले गया और नवादा शामिल हैं।
- ये मार्ग कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक हैं। क्षमता बढ़ने से 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।
- तेल आयात 5 करोड़ लीटर घटाएगा। CO_2 उत्सर्जन 24 करोड़ किलोग्राम कम करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।■

कैबिनेट के निर्णयों पर विस्तृत जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

अब समुद्र तट बनेंगे भारत की समृद्धि के द्वार

करीब 7,500 किमी लंबी समुद्री तटरेखा और 20 हजार किमी से ज्यादा लंबा जलमार्ग...भारत के लिए यह सिर्फ आंकड़े भर नहीं, बल्कि 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करने का रास्ता भी है। इसी विजन के साथ बीते 11 साल में लगातार किया गया काम केंद्र सरकार की कोशिशों का उदाहरण बना है तो इस बार 20 सितंबर को इसका निमित्त बना गुजरात का भावनगर, जहां 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सौगातों के साथ पीएम मोदी ने दिया समुद्र से समृद्धि का मंत्र...

आजादी से पहले भारत सदियों तक एक प्रमुख समुद्री ताकत के साथ जहाज निर्माण का बड़ा केंद्र हुआ करता था। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार को गति देते थे। आजादी के बाद भारत के पास अपनी इस विरासत का उपयोग करने का बेहतरीन अवसर था लेकिन, इसकी बजाय वह दूसरे देशों पर निर्भर होता चला गया। कुप्रबंधन और कुनीतियों का असर यह हुआ कि 50 साल पहले तक जो भारत निर्यात-आयात के लिए 40% स्वदेशी जहाजों का इस्तेमाल करता था, वह घटकर 5% पर रह गया।

विदेश पर निर्भरता के इस उदाहरण का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में आयोजित 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि आज भारत हर साल लगभग छह लाख करोड़ रुपये विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए किराये के तौर पर देता है। यह भारत के आज के रक्षा बजट के लगभग बराबर है। सात दशक में इसी पैसे से विदेशों में लाखों नौकरियां बनी हैं।

गुजरात की धरती से देश को सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी दर्जनभर से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें शामिल हैं...

1 मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल

इसे क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है।

4.15 लाख वर्ग फुट में फैला यह टर्मिनल।

10 हजार यात्रियों और हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है।

यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जहां एक साथ 5 क्रूज शिप खड़े हो सकेंगे।

72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं इसमें।

2 कोलकाता पोर्ट में नए कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास: पूर्वी भारत के व्यापारिक और समुद्री गतिविधियों में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

3 पारादीप पोर्ट (ओडिशा) में नए कार्गो बर्थ और आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग सुविधा: इस परियोजना से ओडिशा के पोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार सुगमता में सुधार होगा।

4 कांडला के तूना टेकरा में मल्टी-कार्गो टर्मिनल: यह पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार में वृद्धि लाएगा।

5 चेन्नई पोर्ट और कार निकोबार द्वीप में सी-वॉल का निर्माण: तटीय सुरक्षा और समुद्री कटाव के लिए यह परियोजना अहम है।

6 कांडला पोर्ट में मल्टी-कार्गो टर्मिनल और ग्रीन बायो-मिथेनॉल प्लांट: यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है। पोर्ट के व्यापारिक कार्यों को बढ़ावा देगी।

7 पटना और वाराणसी में जलमार्ग सुविधाओं का विस्तार: अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से व्यापार और माल ढुलाई में सुधार होगा।

26,354 करोड़ रुपये की लागत वाली गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया।

- इनमें छारा बंदरगाह, आईओसीएल रिफाइनरी, 600 मेगावाट की सोलर परियोजना, धोलेरा क्षेत्र के पूर्ण नेटवर्क समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं।

दूसरे देशों पर निर्भरता भारत की दुश्मन

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है- दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता।

चिप हो या शिप... आत्मनिर्भरता ही विकल्प

आत्मनिर्भरता को विकसित राष्ट्र का संकल्प बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक अगर हमें विकसित होना है तो आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसके अलावा भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है। चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे।

पीएम मोदी ने समुद्री क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को वापस हासिल करने की दिशा में बीते 11 वर्षों में किए गए प्रयासों के साथ भविष्य के विजन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रिसर्च बताते हैं कि जहाज निर्माण की दिशा में होने वाले हर एक रुपये के निवेश से अर्थव्यवस्था में लगभग दोगुना रिटर्न आता है। शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक नौकरी-रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती हैं। यानी कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में 600 से अधिक नौकरी सृजित होती हैं। इसलिए, अब हम देशभर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं।

भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी दोगुनी कर ली है। 2014 से पहले भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन था जो अब एक दिन से कम हो गया है। नए और बड़े पोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। भारत 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहता है। केंद्र सरकार का यह प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

आत्मनिर्भर महिला

राष्ट्र की प्रगति का आधार

स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला सिर्फ परिवार ही नहीं, राष्ट्र की प्रगति का आधार भी होती है। यही सोच बीते 11 साल में केंद्र सरकार की उन नीतियों में भी दिखाई दी है, जिन्होंने महिलाओं की भूमिका को सिर्फ लाभार्थियों से सक्रिय राष्ट्र निर्माता के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। महिला सशक्तिकरण के रास्ते नए भारत के निर्माण का साक्षी इस बार मध्यप्रदेश का धार जिला बना, जहां सृजनशीलता और नवाचार की परंपरा के संस्थापक भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की तो साथ ही देश के पहले एकीकृत टेक्सटाइल पार्क की रखी नींव...

भारत सरकार ने जीवन के हर पहलू पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून से लेकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छ भारत, पोषण अभियान, उज्ज्वला और मुद्रा जैसी योजनाओं ने आत्मसम्मान को बढ़ाया है तो राजस्थान के झुंझुनू में 8 मार्च 2018 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान ने कुपोषण से लड़ने का नया हौसला दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वस्थ बनाने की इसी कड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को धार से आगे बढ़ाया। स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के साथ 8वें पोषण अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक मां स्वस्थ होती है तो पूरा घर सुचारू रूप से चलता है और अगर वह बीमार पड़ती है तो पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो जाता है। 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान के तहत हाइपरटेंशन और मधुमेह से लेकर एनीमिया, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। सभी जांच और दवाएं भी निःशुल्क दी जाएंगी। [illegible]

...ताकि जच्चा-बच्चा सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

वैश्विक टेक्सटाइल हब की ओर एक और कदम

देश के कुल निर्यात में 9 फीसदी हिस्सेदारी के साथ टेक्सटाइल सेक्टर कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है। [illegible] वर्ष 2030 तक कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा [illegible] का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पीएम मोदी ने फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन के [illegible] इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क (पीएम मित्र पार्क) की आधारशिला...

[illegible]

महिलाओं को मिलेंगे 60% रोजगार

- [illegible]
- [illegible]

[illegible] मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य के साथ 2017 में शुरू की गई मातृ वंदना योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके तहत पहली संतान के जन्म पर 5 हजार और दूसरी बेटी के जन्म पर 6 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। 17 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में भी 15 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं के खाते में 450 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई।

[illegible]

पूर्वोत्तर की प्रगति भारत की समृद्धि

नागरिक देवो भव: के मूलमंत्र पर चल रहा देश पूर्वोत्तर के आठों राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजता है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए बजट चार गुना बढ़ाया गया तो यहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी एवं डिलीवरी केंद्र सरकार की पहचान बन गई। आज पूर्वोत्तर देश के विकास का ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों का शुभारंभ किया तो वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का किया उद्घाटन...

भारत सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसे हासिल करने के लिए देश के सभी राज्यों को विकसित बनाना होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ईटानगर में विकास कार्यों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तवांग मठ से लेकर नामसाई के स्वर्ण पगोडा तक अरुणाचल प्रदेश शांति और संस्कृति का संगम है। देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश को ही मिलती हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि त्वरित विकास की किरणों को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए। प्रदेश को पिछले एक दशक से देश के विकास के साथ जोड़ा गया है। इसे आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने राज्य को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़ी योजनाओं की सौगात दी। ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की व उनके स्थानीय उत्पादों को देखा।

नवरात्रि के पहले दिन और दिव्य दुर्गा पूजा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में

प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की पहले की सरकारों पर यह प्रहार किया कि अरुणाचल जैसे राज्यों ने बेहतर नहीं सोचा। उन्होंने कहा, सीटें कम होने से ज्यादा से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता और न ही यहां ध्यान होता। यही कारण है कि 2014 के बाद से अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ आए और चले गए, बल्कि रात भी रुके, उनका प्रयास रहा कि वो दूर-दराज के क्षेत्रों, जिलों और गांवों में जाएं। पीएम मोदी खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर गए हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने शांति स्थापना में मदद की, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिली।

ईटानगर में अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला

- ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं (240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना और 186 मेगावाट की टातो-I जलविद्युत परियोजना) की आधारशिला रखी गई।
- तवांग में 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाले एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। तवांग जिले में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करेगा।
- 1,290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन।

16 गुना से ज्यादा मिली हिस्सेदारी

2004-2014 के बीच 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय टैक्स में से सिर्फ 6 हजार करोड़ रुपये ही मिले थे। जबकि 2014 से 2024 के 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपये मिले।

माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने व संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती देने की कड़ी में 'प्रसाद' योजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 51 शक्तिपीठों में शामिल यह प्राचीन मंदिर त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित है। इस परियोजना को ऊपर से कछुए का आकार दिया गया है। मंदिर परिसर में मार्ग, नए द्वार, पुनर्निर्मित प्रवेश द्वार और बाड़, जल निकासी व्यवस्था, स्टॉल, ध्यान कक्ष, अतिथि आवास, कार्यालय कक्ष सहित एक नया तीन मंजिला परिसर का निर्माण किया गया है। इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायता होगी।

> अरुणाचल की भूमि, उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के ज्वार की भी धरती है। जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य और सादगी का प्रतीक है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पूजा-अर्चना की और सभी भारतीयों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर में प्रार्थना करें और त्रिपुरा की सुंदरता का भी लुत्फ उठाएं।

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन देखने के लिए यह कोड स्कैन करें

स्वच्छ ऊर्जा से दौड़ेगी विकास की गाड़ी

देश को विकसित राष्ट्र बनाने के जिस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा और समाज के सभी वर्गों का हित उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। यही कारण है कि अंत्योदय का विज़न आज केंद्र सरकार का मिशन बन गया है। सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सभी के उत्थान के लिए काम हो रहा है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के विकास को भी मिलेगी नई ताकत...

तकनीक और आधुनिक उद्योग-धंधों के जमाने में विकास की गाड़ी आज बिजली से ही दौड़ रही है। बिजली है, तो उजाला है, गति और प्रगति है। बिजली है, तो [illegible] और दुनिया जुड़ रही है। यही कारण है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनी तो [illegible] सरकार ने संकल्प के तहत देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई। जहां-जहां बिजली पहुंची, वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए-नए उद्योग-धंधे स्थापित हुए। [illegible] की अमर गाथाएं और [illegible] संस्कृति की सुगंध [illegible] वाले राजस्थान के बांसवाड़ा में विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपनी बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। यही नहीं, इसमें भी सबसे अच्छा वही देश होगा जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे होगा। इसलिए भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा अभियान को एक जन-आंदोलन बनाकर काम कर रही है।

दुनिया भर में ऊर्जा [illegible] परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस परिवर्तन में भारत एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सौर और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। [illegible] ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के दौर में [illegible] स्थापित हुआ है। 25 सितंबर को राजस्थान की धरती से बिजली [illegible] नया अध्याय लिखा गया। एक दिन में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए [illegible] की बिजली परियोजनाएं शुरू की गईं। यह दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस अभियान में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

'सबका साथ-सबका विकास' का [illegible] केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर [illegible] [illegible]

तेज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा राजस्थान

- 42,000 करोड़ रुपये की लागत से अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (4x700 मेगावाट) की आधारशिला।
- 19,210 करोड़ रु. की लागत से राजस्थान में हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। फलौदी, जैसलमेर, जालोर, सीकर में सौर परियोजना का उद्घाटन और बीकानेर में आधारशिला।
- 13,180 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की तीन विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं का शिलान्यास। वर्ष 2030 तक 10.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह होगी सिद्धि।
- बीकानेर और बांसवाड़ा में ग्रिड सब स्टेशन की आधारशिला। डूंगरपुर जिले के लिए 220 केवी ट्रांसमिशन का उद्घाटन।
- राजस्थान में 20,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई जल संसाधन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन।
- 2,880 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, जालोर, भीलवाड़ा जिले के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला।
- भरतपुर शहर में फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल और 116 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं का शिलान्यास।
- 2,630 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से संबंधित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन।
- जयपुर में 210 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल, जयपुर में आईटी विकास और ई-गवर्नेंस केंद्र का उद्घाटन।
- बीकानेर-दिल्ली कैंट और जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी।
- राजस्थान के सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित।

16,050
करोड़ रुपये

से अधिक की लागत से 1,??? मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत शुरू की गई इन परियोजनाओं से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलेगा लाभ।

[illegible]

> “डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राजस्थान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बांसवाड़ा से हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रदेश की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
>
> –नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

...की संकल्प और राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा' के मूलमंत्र को जीने वाले पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सब अब हकीकत बन रहे हैं। आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, यह देश का संकल्प है।

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

खाद्य क्षेत्र में भारत अब दुनिया का साझेदार

दुनिया में दूध, प्याज, दालों का सबसे बड़ा और फलों-सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के मामले में भी भारत ने एक दशक में बड़ी छाप छोड़ी है। 'दुनिया का बाजार' से 'दुनिया का साझेदार' में बदली यह भूमिका केंद्र सरकार की उस रीति-नीति का परिणाम है, जिसकी नींव 2014 से व्यापक रिफॉर्म्स के साथ तैयार की गई। खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की सफलता की इसी कहानी के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से किया भारत में निवेश का आह्वान...

वर्ष 2014 से भारत ने उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की शुरुआत की, जहां संभावनाएं तो अपार थीं लेकिन व्यापक रिफॉर्म्स के साथ उन्हें पर्याप्त समर्थन की जरूरत थी। खाद्य क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक होने के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निर्यात का ग्लोबल हब बनने की भारत की महत्वाकांक्षा ऐसे ही एक सपने की शुरुआत थी। 100% एफडीआई से लेकर पीएलआई और पीएम किसान संपदा योजना से व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तक केंद्र सरकार ने परिवर्तन की एक नई कहानी लिखी जो सफलता के आंकड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को सही साबित किया। भारत के कुल कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% के मुकाबले 2023-24 में 20.4% तक पहुंची। इससे यह भी साबित किया है कि भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है, वह अभूतपूर्व ही नहीं, अकल्पनीय भी है।

वैश्विक खाद्य हब बनने के भारत के इसी दृष्टिकोण को पीएम मोदी ने 25 सितंबर को नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में सबके सामने

भारत के पास डायवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति

प्रधानमंत्री मोदी ने डायवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति के साथ खाद्य क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को विस्तार दिया। साथ ही, इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को भी किया साझा...

अपार क्षमता और संभावना

कहीं भी निवेश करने से पहले हर निवेशक उस जगह की क्षमताओं को देखता है। भारत आगे [illegible] क्योंकि यहां हर अवसर, हर पल और हर जरूरत की [illegible] होती है। [illegible] दुनिया में दूसरे स्थान पर है। फल, सब्जी और मछली उत्पादन में भी भारत का [illegible] रहा है। आज जब दुनिया में [illegible] पर संकट आता है, सप्लाई चेन में [illegible] आता है तो भारत मजबूती से [illegible] है।

प्रतिस्पर्धा में बढ़त

भारत में हर सौ किलोमीटर पर खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। इसलिए यहां जबरदस्त डिमांड है। यह भारत को प्रतिस्पर्धा में बढ़त देती है। पिछले 10 सालों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये वो आकांक्षी वर्ग है जो देश में डिमांड को बढ़ा रहे हैं।

नीतियों का समर्थन

सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए इसमें 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। पीएलआई स्कीम और मेगा फूड पार्कों के विस्तार से इस सेक्टर को मदद मिली है। लाखों फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है। [illegible] सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। जीएसटी रिफॉर्म से इस सेक्टर को काफी छूट दी गई है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश भारत में कृषि और फूड सेक्टर से जुड़े कई स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

एफपीओ और सहकारिता की ताकत

देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ [illegible] 5 हजार से ज्यादा [illegible] उपलब्ध [illegible] है। [illegible] हिमाचल [illegible] बिहार का [illegible] महाराष्ट्र के [illegible] कृषि उत्पादों को [illegible] पहुंचा रहा है। सहकारिता क्षेत्र की [illegible] डेयरी सेक्टर [illegible] कर रहा है।

रहा। उन्होंने कहा कि आज देश का [illegible] फूड इस सेक्टर में [illegible] है। भारत में डिमांड, [illegible] और [illegible] सब कुछ मौजूद है। ये सारी चीजें भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक [illegible] बनाती हैं। पीएम मोदी ने [illegible] कहा कि निवेश के साथ भारत में विस्तार का सही समय है, [illegible] समय है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दौरान 1.02 लाख करोड़ रुपये की निवेश [illegible] हुए। इनसे 64,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें

परमाणु ऊर्जा जनकल्याण का मार्ग

वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का विशेष महत्व है, क्योंकि सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के इस सबसे शक्तिशाली स्रोत का उपयोग बिजली उत्पादन के साथ चिकित्सा, उद्योग और वैज्ञानिक शोध में कर जनकल्याण को दे रहा है लगातार बढ़ावा...

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार बड़ी पहल कर रहा है। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली उत्पादन क्षमता में एक दशक में 90 फीसदी की बढ़ोतरी और स्थापित परमाणु क्षमता में 71% की वृद्धि जैसे आंकड़े भारत के दृष्टिकोण को बयान करते हैं तो वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पर परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी का लक्ष्य इस दिशा में प्रतिबद्धता की कहानी कह रहा है। इसी को ध्यान में रखकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक निवेश किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं चालू वित्त वर्ष के बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास और 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़े कुछ अधिनियमों में संशोधन करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। परमाणु ऊर्जा विकास में तेजी लाने वाले परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करेगा।

राजस्थान में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला

राजस्थान के माही-बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। ऊर्जा के लिए स्वच्छ, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के बिजली क्षेत्र को बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की इस परमाणु ऊर्जा परियोजना (4X700 मेगावाट) की लागत लगभग 42 हजार करोड़ रुपये है। यह देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा जो विश्वसनीय आधार भार (बेसलोड) ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। यह पर्यावरण संरक्षण और विकसित परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूती देगा। आत्मनिर्भर भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा डिजाइन और विकसित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ चार स्वदेशी 700 मेगावाट दाबानुकूलित भारी पानी रिएक्टर शामिल

सामाजिक भलाई का साधन बनती परमाणु ऊर्जा

केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रगति के तहत कई ऐसी तकनीक विकसित की है जो आमजन के लिए लाभदायक हैं और समाज की भलाई करती हैं। इसमें नाभिकीय कृषि और खाद्य संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, जल शुद्धिकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और हाइड्रोजन उत्पादन है शामिल...

नाभिकीय विद्युत ऊर्जा

नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से लगभग [illegible] मिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया गया जो देश में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 3% है। इससे अतिरिक्त लगभग [illegible] मिलियन टन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ। वर्ष 2024-25 के दौरान नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से बिजली का औसत खर्च [illegible] रुपये प्रति यूनिट रहा।

नाभिकीय कृषि और खाद्य संरक्षण

विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके फसल सुधार और खाद्य संरक्षण की क्षमता बढ़ रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने रेडिएशन की सहायता से तिलहन, दलहन, चावल, जूट, गेहूं और [illegible] फसलों की किस्में जारी की हैं। वहीं, विकिरण आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य पदार्थों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने, संक्रमित जीवाणु समाप्त करने और किसी को बढ़ने देने के लिए किया जाता है।

शुष्क क्षेत्रों में कृषि का सहयोगी

पर्यावरण अनुकूल सेल्यूलोज-आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया गया है जो अपने वजन से 500 गुना पानी को अवशोषित कर सकता है। यह शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए इस्तेमाल किया गया है।

चिकित्सा और जीव विज्ञान

- नाभिकीय चिकित्सा में रेडियो आइसोटोप का उपयोग थायराइड रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी रोग सहित कई प्रकार के कैंसर व कई तरह के ट्यूमर के उपचार में किया जाता है।
- स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान वाली स्वदेशी 'प्रौद्योगिकी' का ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी कारगर साबित हुई है।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बोन कैंसर के उपचार के लिए अंतर विकल्प के रूप में स्वदेशी व किफायती [illegible] विकसित की है।

है। यह भारत की स्वदेशी 'फ्लीट मोड' पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे भारत में एक समान डिजाइन और खरीद योजनाओं के तहत 10 समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई पर लेकर जा रहा है।

भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास से वर्ष 2031-2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता जो वर्तमान में 8,880 मेगावाट है, बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2013-14 में यह महज 4,780 मेगावाट थी। इस क्षेत्र को विस्तार देने की कड़ी में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा कुल 15,300 मेगावाट क्षमता के 21 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन के विभिन्न चरणों में हैं। वहीं, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सहित कुल 7,300 मेगावाट क्षमता के नौ और रिएक्टर भी निर्माणाधीन हैं।■

71वां
राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार

मोहनलाल को दादा साहब फाल्के

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन कलाकारों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी प्रतिभा से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। समारोह में बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक मोहनलाल को चार दशकों से अधिक समय तक सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया...

भारत में सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में शुरू किए गए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने न केवल सिनेमाई प्रतिभा को पहचान दी है, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक छवि को आकार देने वाली विविध संस्कृतियों और कहानियों को भी आगे बढ़ाया है। अभिनेता मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि उन्होंने न केवल अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को भी अक्षुण्ण रखा है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए, मोहनलाल ने सिनेमा में अपने सफर को आकार देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद

तैयार किए जा रहे हैं मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स

देश का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान (आईआईसीटी) मुंबई फिल्म [illegible] परिसर में काम शुरू कर चुका है। यह गेमिंग, एनिमेशन, [illegible] और [illegible] सहित प्रमुख वैश्विक कंपनियों के सहयोग से 17 पाठ्यक्रम पहले से ही चला रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि [illegible] स्टेट [illegible] के रूप में [illegible] राज्यों के [illegible] के दृष्टिकोण से [illegible] को बढ़ावा देने और [illegible] को मजबूत करने के लिए [illegible] के उद्देश्य को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स तैयार किए जा रहे हैं जो 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हैं। इस काम में [illegible] महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किया। पुरस्कार को 'जादुई और पवित्र' बताते हुए, उन्होंने इसे मलयालम फिल्म उद्योग के दिग्गज कलाकारों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सिनेमा उनकी आत्मा की धड़कन है। इस सम्मान ने इस कला को और गहराई व प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है।

भारत में सिनेमा लोकतंत्र के स्तर और भारत की विविधता को दर्शाता है। जिस प्रकार अनेक भारतीय भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ है, उसी प्रकार सिनेमा भी भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि समाज को जागृत करने, संवेदनशीलता पैदा करने और मुद्दों में जागरूकता फैलाने का माध्यम भी बनती हैं। उन्होंने सिनेमा में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का उल्लेख करते हुए, कहा कि समान अवसर मिलने पर वह उत्कृष्टता और असाधारण सफलता प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने और अधिक सक्रिय महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अभिनेता शाहरुख खान को उनकी 'जवान' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया, तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं अभिनेता विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने बच्चों, युवा और उभरती प्रतिभाओं के योगदान की सराहना की जो फिल्म उद्योग में रचनात्मकता व नवीनता ला रहे हैं। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। सिनेमा में दिखाई जाने वाली पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी स्वागत किया।•

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

द कॉमन मैन

जन्म : 24 अक्टूबर 1921 ■ मृत्यु : 26 जनवरी 2015

अपने कार्टून चरित्र 'कॉमन मैन' के ज़रिए मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को खूबसूरती से उकेरने का काम किया। महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने के लिए उन्होंने न केवल हास्य को माध्यम बनाया बल्कि जनता को याद दिलाया कि सत्ता में बैठे लोग भी इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित लक्ष्मण अपने कार्टूनों के माध्यम से राष्ट्र की अंतरात्मा के निरंतर प्रहरी बने रहे। आम आदमी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आरके लक्ष्मण भारत की जनता के लिए सदैव रहेंगे अविस्मरणीय...

एक ज़माना था जब देश के हवाई अड्डों में महाराजा का एक बड़ा सा सिंबल होता था। एक व्यक्ति का ध्यान इस ओर गया तो उसने सोचा कि जमाना बदल गया फिर भी यहां महाराजा का सिंबल क्यों है? लक्ष्मण का कॉमन मैन क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे लोग क्यों नहीं बदलने चाहिए? वे व्यक्ति एविएशन मंत्री के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। उनकी बात तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची। उस समय एक निर्णय लिया गया और एयरलाइन कंपनी ने महाराजा को हटा कर कॉमन मैन का चित्र लगाया। महाराजा की तस्वीर को कॉमन मैन से बदलवाने का प्रस्ताव करने वाला वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी उड़ान योजना के माध्यम से आम लोगों तक हवाई जहाज को ले आए। पेंटिंग तक सीमित आरके लक्ष्मण के कॉमन मैन का विचार पीएम मोदी के भीतर जीवित था और जब उन्हें काम करने का मौका मिला तो उन्होंने सपना देखा कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में घूमे।

इतना ही नहीं, पहले के जमाने में ईज ऑफ लिविंग जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। उस दौर में प्रभाव वाले लोग सुविधाओं के पहले बड़े हकदार बन गए थे। बीच में पिसता था देश का सामान्य नागरिक जो आरके लक्ष्मण के कार्टूनों में झलकता है। इस कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा और उस दिशा में काम किया। साथ ही, सरकार ने यह भी तय किया कि अगर कॉमन मैन ने समाज और देश के लिए कुछ किया है तो उसे पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है।

कार्टून से तत्कालीन कटाक्ष करने वाले आरके लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे। वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक मन थे। उनके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे। उसका प्रकटीकरण उनकी रचनात्मकता से हुआ करता था। कलम और पैंसिल के धनी लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को हुआ था। उनका पूरा नाम रासिपुरम कृष्णास्वामी अय्यर लक्ष्मण था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाले कार्टून में उन्होंने कॉमन मैन का चित्रण ऐसे किया कि हर हिंदुस्तानी को लगता रहा कि यह मैं हूं। उस कॉमन मैन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान के किस इलाके या किस युग का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण के कॉमन मैन के चेहरे में आधुनिकता है, उसकी झुर्रियों में दम है लेकिन चश्मे के बिना जिंदगी नहीं चलती है।

26 जनवरी 2015 को आरके लक्ष्मण का निधन हो गया। वे चले गए, पर उनका कॉमन मैन आज भी जिंदा है। 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आरके लक्ष्मण पर आधारित कॉफी टेबल बुक 'टाइमलेस लक्ष्मण' का विमोचन किया था। साथ ही उन्होंने 2022 में पुणे के बालेवाड़ी में निर्मित आरके लक्ष्मण आर्ट गैलरी-संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। लक्ष्मण के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "आरके लक्ष्मण, भारत आपको याद करता रहेगा। हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी हास्य जोड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी कृतियां हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती हैं।" ■

प्रधानमंत्री का पत्र

मेरे प्यारे देशवासियों

नमस्कार।

[illegible]

[illegible] Next Generation GST Reforms [illegible] 'GST बचत उत्सव' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नरेंद्र मोदी

जीएसटी बचत

उत्सव

22 सितंबर, नवरात्रि के प्रथम दिवस पर सूर्योदय के साथ ही देशभर में शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की बचत, सुविधा और समृद्धि का पर्व है।

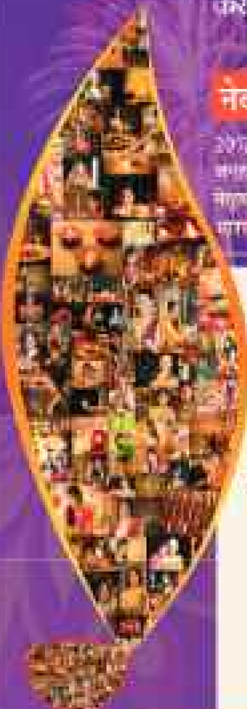

नेक्स्ट जेन जीएसटी

2017 से पहले अलग-अलग टैक्स व्यवस्था से अलग परेशानी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू हुआ एक देश-एक कर, आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार।

अब मुख्य रूप से दो ही स्लैब...

5%,18%

मतलब है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएंगी।

न्यू इंडिया समाचार

आर.एन.आई. DELHIN/2020/78812, 16-31 अक्टूबर, 2025